सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष–01 अंक–35 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, सोमवार 23 फरवरी 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए,

सु-विचार

परिस्थितिया जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि.. स्वभाव और सम्बंध काम आते है...!

अज्ञात...

खैरागढ़ में 'खेत बनाम फैक्ट्री' की जंग ; क्या पुलिसिया कार्रवाई से दबेगा किसानों का आंदोलन?

नरेन्द्र डाकलिया / खैरागढ़-छुईखदान

छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री (श्री सीमेंट) को लेकर उपजा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां कॉरपोरेट घराने और प्रशासन विकास का हवाला देकर प्लांट लगाने पर आमादा हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों किसान अपनी उपजाऊ जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए 'आर-पार' की लड़ाई लड़ रहे हैं।

आंदोलन की जड़ : उपजाऊ भूमि और जल संकट का डर

विवाद का मुख्य केंद्र जालबांधा और छुईखदान क्षेत्र के लगभग 40-45 गांव हैं। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन पर फैक्ट्री प्रस्तावित है, वह बेहद उपजाऊ है। पर्यावरणः ग्रामीणों को डर है कि सीमेंट की धूल उनकी फसलों और स्वास्थ्य को तबाह कर देगी। जल स्तरः फैक्ट्री द्वारा भारी मात्रा में भूजल दोहन से क्षेत्र में खेती के लिए पानी का संकट पैदा हो जाएगा।

पुलिस की 'रणनीति' और ग्रामीणों का संगीन आरोप

आंदोलनकारियों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा पुलिस और प्रशासन की संदिग्ध कार्यप्रणाली को लेकर है। किसान नेताओं का दावा है कि प्रशासन 'दमनकारी नीति' अपना रहा हैः फर्जी मुकदमों का डरः ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस उन पर पुराने

अज्ञात आरोपी में बेकसूर के नाम जोड़, नेतृत्व को भेजेंगे जेल, इधर जन सुनवाई का होगा खेल?

मामलों या प्रदर्शन के दौरान अज्ञात नाम से दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर "फर्जी आरोपी" बनाने की तैयारी में है। नेतृत्व विहीन करने की साजिशः आंदोलनकारियों का मानना है कि यदि मुख्य नेताओं को फर्जी आरोपों के आधार पर जेल भेज दिया जाता है, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसका फायदा उठाकर प्रशासन आनन-फानन में फर्जी जनसुनवाई कराकर फैक्ट्री के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कर सकता है।

'दिसंबर का संग्राम' व स्थगित जनसुनवाई

बीते 11 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित जनसुनवाई के दौरान जो मंजर दिखा, उसने प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए थे। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतर आए थे। भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स के बावजूद किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ, जिसके कारण प्रशासन को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जनसुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

हालांकि यह विशुद्ध रूप से एक किसान आंदोलन है, लेकिन चुनाव और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। विपक्ष इसे सरकार की 'किसान विरोधी' नीति बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष रोजगार और विकास के नाम पर बचाव की मुद्रा में है।

ग्राम सभाओं की 'संवैधानिक' ढाल

प्रशासन की संभावित कार्रवाई को देखते हुए किसानों ने भी अपनी रणनीति बदली है। अब यह आंदोलन किसी एक नेता के भरोसे नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चल रहा हैः **ग्राम सभा प्रस्तावः** प्रभावित गांवों ने अपनी ग्राम सभाओं में फैक्ट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे कानूनी रूप से चुनौती दी है। **महिला शक्तिः** इस बार आंदोलन की कमान पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी संभाली है, ताकि पुलिसिया कार्रवाई का मुकाबला किया जा सके।

वर्तमान स्थिति : खैरागढ़ का यह इलाका इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ कॉरपोरेट दबाव है, तो दूसरी तरफ अपनी माटी से जुड़ा किसान। यदि प्रशासन जबरन जनसुनवाई कराने या नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है, तो स्थिति और भी उग्र हो सकती है। मुख्य मांगः किसानों की एक ही मांग है– "हमें फैक्ट्री नहीं, अपनी खेती और शुद्ध हवा चाहिए।"

पूर्व विधायक गिरफ्तार व मुचलके पर रिहा

खैरागढ़ प्रकरण: पुलिस की कार्यशैली पर उठे तीखे सवाल

खैरागढ़ की राजनीति में हलचल : महिला नेत्री की शिकायत पर पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

'एफआईआर को खैरागढ़ जिला पुलिस ने रखा संवेदनशील श्रेणी में'

खैरागढ़

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

पुलिस की खामोशी

जांच पर नजर

आंदोलन से जुड़ा बताया जा रहा है विवाद

आलोक तिवारी / भिलाई-राजनांदगांव

खैरागढ़ के पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामले ने जहां राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, वहीं अब पुलिस विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। महिला नेत्री की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने, गिरफ्तारी और फिर उसी दिन मुचलके पर रिहाई के घटनाक्रम ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है।

देरी और गोपनीयता पर प्रश्न : सूत्र बताते हैं कि शिकायत जनवरी के मध्य में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दी गई थी, जबकि एफआईआर 2 फरवरी को दर्ज हुई। इस अंतराल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रारंभिक जांच में असामान्य विलंब हुआ? यदि मामला महिला की निजता और डिजिटल अपराध से जुड़ा था, तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? इसके अतिरिक्त प्रकरण को संवेदनशील श्रेणी में रखकर पोर्टल पर सीमित पहुंच में डालना भी चर्चा का विषय बना है। आम तौर पर गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों की बुनियादी जानकारी सार्वजनिक रहती है। ऐसे में गोपनीयता की आड़ में पारदर्शिता सीमित किए जाने के आरोप लग रहे हैं।

गिरफ्तारी और तत्काल रिहाईः एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी और फिर उसी दिन मुचलके पर रिहाई–इस क्रम ने भी जनचर्चा को हवा दी है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में यह प्रक्रिया वैधानिक है, लेकिन विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का तर्क है कि पुलिस को जांच की गंभीरता का स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करना चाहिए था ताकि भ्रम और अविश्वास की स्थिति न बने।

क्या समान व्यवहार होता ? : सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि यदि आरोपी कोई सामान्य नागरिक होता तो क्या पुलिस की प्रक्रिया और रवैया यही रहता? क्या डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच, मोबाइल ट्रेसिंग और पूछताछ की स्थिति सार्वजनिक की गई? अब तक जांच की प्रगति पर स्पष्ट ब्रीफिंग नहीं दी गई है, जिससे संदेह की गुंजाइश बनी हुई है।

पुलिस की भूमिका पर निगाह : जिला पुलिस की कार्यशैली पर भी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है। संवेदनशील मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई विभाग की विश्वसनीयता तय करती है। इस प्रकरण में आधिकारिक मौन और सीमित जानकारी ने विभाग की निष्पक्षता को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

जवाबदेही की मांग : सामाजिक संगठनों और विपक्षी प्रतिनिधियों की मांग है कि– जांच की वतर्मान स्थिति सार्वजनिक की जाए, डिजिटल साक्ष्यों की जांच रिपोर्ट साझा की जाए, और यह स्पष्ट किया जाए कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और दबावमुक्त है। खैरागढ़ का यह मामला अब केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। पुलिस विभाग के सामने चुनौती है कि वह तथ्यों के आधार पर शीघ्र और पारदर्शी जांच पूरी कर जनविश्वास बहाल करे। अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा, किंतु फिलहाल सवालों का घेरा पुलिस के इर्द-गिर्द सिमट आया है।

अयोध्या आंदोलन से प्रेरित, भिलाई की रामनवमी बनी मध्य भारत का सबसे बड़ा आयोजन- पाण्डेय

ध्वजवाहकों का श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने किया सम्मान, 41वें वर्ष की रामनवमी शोभायात्रा में भी शामिल होंगे 1100 से अधिक ध्वजवाहक

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

श्रीराम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा विगत 40 वर्षों से श्रीराम नवमी के पावन अवसर पर निकाली जा रही शोभायात्रा के ध्वजवाहकों का सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया। श्रीरामनवमी उत्सव के 41वें वर्ष के अवसर पर आज श्रीराम चौक, खुर्सीपार मैदान में आयोजित इस सम्मान समारोह में 1100 से अधिक ध्वजवाहकों और झांकी प्रमुखों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप समिति के संरक्षक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 1986 में प्रारंभ हुई श्रीराम जन्मोत्सव समिति की यात्रा आज हजारों ध्वजवाहकों की भव्य शोभायात्रा में बदल चुकी है। प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलते हुए समिति समाज में एकता, आस्था और सेवा का संदेश देती रही है, जिसका प्रतीक ह्यएक मुट्ठी दान झ्र श्रीराम के नामह्व अभियान भी है, जिसकी शुरूआत आज की गई। इस अवसर पर समिति के दिवंगत वरिष्ठ सदस्यों स्व.योगेंद्र पाण्डेय, स्व. अरविंद वर्मा, स्व. बीडी सिंह, स्व. शेरा ढिल्लन एवं स्व. परमजीत सिंह लाड्डी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि 1986 में जब यह आयोजन प्रारंभ हुआ था, तब देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ आज जैसी नहीं थीं। उस समय कुर्सीपार, कैंप, जोरातराई और पुरैना जैसे क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों का स्वरूप था और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संख्या अधिक थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग सनातन धर्म और हिंदू समाज की परंपराओं को अवैज्ञानिक और पिछड़ा बताने का प्रयास करता था। पूजा-पद्धतियों और देवी-देवताओं पर शंका उत्पन्न की जाती थी। इसी समय अयोध्या में जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे देश में हिंदू समाज के जागरण की नींव रखी। भिलाई में भी इसी प्रेरणा से राम जन्मोत्सव समिति का गठन हुआ। प्रारंभिक यात्रा में कुछ दर्जन लोग साइकिल और एक मेटाडोर में प्रभु श्रीराम की तस्वीर लेकर निकले थे, जो आज हजारों ध्वजवाहकों की भव्य शोभायात्रा में परिवर्तित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समिति की यह यात्रा प्रभु श्रीराम की कृपा से निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी इसी भव्यता से रामनवमी का आयोजन होता रहेगा। ध्वजवाहकों के सम्मान के साथ उन्होंने सभी को शुभकामनाएँ दीं।

श्री पाण्डेय ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आज दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है, जहाँ एक वर्ष में 24 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुँचे। इससे क्षेत्रीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ अपने इष्टदेव की आराधना का अधिकार भी उतना ही आवश्यक है। समिति द्वारा चलाए जा रहे ह्लएक मुट्ठी दान झ्र श्रीराम के नामह्व अभियान को भी उन्होंने समाज की एकता और सेवा का प्रतीक बताया। इस अभियान में हर वर्ग के लोग अन्न दान करते हैं, जिससे महाप्रसाद तैयार होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रारंभिक वर्षों में एक साधारण दाल बेचने वाले ने अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु श्रीराम के नाम अर्पित किया था।

कार्यक्रम में उपस्थित श्रीराम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पाण्डेय ने समिति की 40 वर्षों की यात्रा और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक मंदिर की ध्वज यात्रा से प्रारंभ हुआ था और आज तीसरी-चौथी पीढ़ी तक पहुँच चुका है, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्वज लेकर रामलीला मैदान तक पहुँचती है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ ने सौ वर्षों तक समाज सेवा और धर्म के लिए निरंतर कार्य किया है। इसी विचार और ध्येय का एक अंश श्रीराम जन्मोत्सव समिति भी है, जो पिछले 41 वर्षों से भिलाई, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में सबसे बड़े रामनवमी आयोजन के रूप में सनातन धर्म को एकजुट करने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि भिलाई "मिनी इंडिया" है, जहाँ वर्षभर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उनका एकत्रीकरण रामनवमी के दिन समिति द्वारा किया जाता है। हजारों श्रद्धालु मंदिरों से ध्वज लेकर सड़कों पर निकलते हैं और रामलीला मैदान तक पहुँचते हैं, जो सनातन धर्म के सम्मान और एकता का अद्वितीय उदाहरण है। समिति द्वारा तीन वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए 'एक मुट्ठी दान - श्रीराम के नाम' अभियान को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत घर-घर से अन्न संग्रह कर महाप्रसाद तैयार किया जाता है और श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। उन्होंने सभी ध्वजवाहकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी और आह्वान किया कि आने वाले दिनों में समिति के सदस्य और समाज के लोग घर-घर पहुँचकर इस अभियान को सफल बनाएं और 26 मार्च को होने वाले रामनवमी महोत्सव को भव्यता प्रदान करें। प्रभु श्रीराम और हनुमान जी की कृपा से यह आयोजन निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहेगा।

इस अवसर पर श्रीराम जन्मोत्सव समिति के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश माने ने कहा कि आज मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में श्री राम जन्मोत्सव समिति के श्रीरामनवमी उत्सव ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। यह समस्त भिलाइवासियों के बहुमूल्य सहयोग एवं हमारे ध्वज प्रमुखों की अगुवाई में सार्थक हुआ है। प्रांतीय महामंत्री बुद्धन ठाकुर ने कहा कि श्रीरामनवमी का यह उत्सव करोड़ों देशवासियों के आस्था एवं प्रभु श्रीराम के प्रति अनन्य आस्था का प्रतीक है जो हमारी गौरवशाली सनातन परंपरा को जीवंत रखे है। कार्यक्रम का संचालन समिति के जिला अध्यक्ष मदन सेन ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से समिति कायर्कारी अध्यक्ष प्रवीण पाण्डेय, विष्णु पाठक, रविन्द्र भगत, लालचंद मौर्य, प्रशांत पाण्डेय, बसंत प्रधान, जोगिंदर शर्मा, संजय दानी, मुरलीधर अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह, रोहित साहू, महिला शाखा अध्यक्ष श्रीमती शीला वाघमारे , श्रीमती मेघा कौर, गीतांजलि कौशिक, तिलकराज यादव, बी पद्मनाभम, गोल्डी सोनी, गारगी शंकर मिश्र, रिंकू साहू, संजय साहू, मेवालाल यादव, धर्मेंद्र भगत, श्रीमती गिरीजा बंछोर, श्रीमती शकुंतला साहू, श्रीमती ईश्वरी नेताम सहित सहित हजारों की संख्या में रामभक्त एवं समिति के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे।

समिति का सफर भी वनगमन जैसा रहा - पाण्डेय

श्री पाण्डेय ने समिति की यात्रा को प्रभु श्रीराम के वनगमन से जोड़ा और कहा कि जैसे रामजी की यात्रा में साधु-संतों के साथ असुर भी मिले, वैसे ही समिति की यात्रा में भी चुनौतियाँ आई, लेकिन यह प्रवाह निरंतर चलता रहा। उन्होंने बताया कि आज समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। प्रभु श्रीराम ने सदैव समाज को प्रथम रखा और समिति भी उसी आदर्श पर कार्य करती है, ताकि जाति, भाषा और समुदाय के भेद मिटाकर एकता का संदेश दिया जा सके।

जनआक्रोश | पुलिस की भूमिका और अवैध शराब पर उठे बड़े सवाल

राजनांदगांव में सियासी तकरार तेज: पुतला दहन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव की राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा की प्रेस विज्ञप्ति ने कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और अवैध शराब के मुद्दे को एक साथ केंद्र में ला दिया। विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के पुतला दहन की घटना के संदर्भ में पुलिस की भूमिका पर तीखे प्रश्न उठाए गए, वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कथित अवैध एवं मिलावटी शराब की बिक्री को जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया गया।

पार्षद ने सार्वजनिक स्थल पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाए जाने को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से 'गंभीर विषय' बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समय रहते प्रभावी कदम अपेक्षित थे। उनके अनुसार, यदि समय पर सख्ती बरती जाती तो स्थिति को टाला जा सकता था। यहां यह कहना कि पुलिस को कांग्रेस ने साध लिया था यानी भाजपा सरकार पुलिस सुनती कांग्रेस पार्टी की इस बयान ने राजनीतिक हलकों में बहस को और तीखा कर दिया है।

विज्ञप्ति का दूसरा अहम बिंदु अवैध शराब का मुद्दा रहा। शिव वर्मा ने दावा किया कि 'गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले' में शराब की उपलब्धता प्रशासनिक सतर्कता आबकारी विभाग, पुलिस और प्रशासन के कार्यक्षमता के साथ साथ उनके भ्रष्ट होने का भी सीधा सीधा आरोप जड़ दिया सरकार की कमजोरी भी गिना रहा है, उस पर प्रश्नचिह्न लगाती है। उन्होंने विशेष रूप से घटिया, कच्ची और मिलावटी शराब के संभावित खतरे का उल्लेख करते हुए इसे जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम बताया। उनका कहना है कि ऐसी शराब से विषाक्तता, बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है, जिस पर सरकार रोकने के बदले खुद ही

अच्छी दारू रोज बेचने ठेलों में गाँव गाँव घर पहुंच सेवा देना चाहिए पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से शिव वर्मा के बताए अनुसार कार्य करना पड़ेगा कड़े कदम उठाने चाहिए।

इन आरोपों के बाद सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने प्रेस विज्ञप्ति में उठाए गए मुद्दों को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सत्तापक्ष के नेताओं का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निरंतर सक्रिय है और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों के बीच भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि अवैध शराब और जन-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ठोस और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है, ताकि शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा व स्वास्थ्य के मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं– क्या आरोपों की जांच होगी, क्या पुतला दहन प्रकरण पर स्पष्टता आएगी, और क्या अवैध एवं मिलावटी शराब पर व्यापक अभियान देखने को मिलेगा। राजनांदगांव में इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय कर सकते हैं।

रिसाली नगर निगम में बड़ा खेल! महापौर परिषद का फैसला पलटा, ठेकेदार को मिली खुली छूट

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली

प्रशासनिक टकराव

कलेक्टर से शिकायत, आयुक्त पर शक्ति दुरुपयोग के आरोप

नगर पालिक निगम रिसाली में सफाई ठेका मामले में बड़ा प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आया है। दस्तावेजों से खुलासा होता है कि महापौर परिषद (MIC) ने 7 जनवरी 2026 को स्पष्ट संकल्प पारित कर नई निविदा प्रक्रिया एक माह में पूर्ण करने और तब तक मौजूदा ठेकेदार को केवल दो माह की सीमित समयवृद्धि देने का निर्णय लिया था। लेकिन इसके बाद जारी आयुक्त के कार्यादेश ने पूरे संकल्प की दिशा ही बदल दी।

क्या बदला और कैसे? : आयुक्त द्वारा जारी आदेश में ठेकेदार को आगामी निविदा जारी होने तक काम जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यानी तय समयसीमा की शर्त व्यवहारिक रूप से हट गई। परिषद का आरोप है कि यह आदेश न केवल उनके संकल्प की भावना के विपरीत है, बल्कि इससे ठेकेदार को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा। महापौर परिषद ने जिला कलेक्टर को भेजी शिकायत में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि निर्वाचित निकाय के निर्णय को प्रशासनिक स्तर पर बदलना अधिकारों का अतिक्रमण है। शिकायत में आरोप है कि आयुक्त ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग कर परिषद के सीमित समय विस्तार को अनिश्चित अवधि में परिवर्तित कर दिया, जिससे प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया प्रभावित हुई।

सवाल जो प्रशासन को घेरे में लेते हैं : जब परिषद ने स्पष्ट समयसीमा तय की थी, तो उसे बदलने का अधिकार किस आधार पर लिया गया? नई निविदा समय पर क्यों नहीं निकाली गई? क्या पुराने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया जानबूझकर लंबित रखी गई?

राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल : रिसाली में यह मामला अब सत्ता बनाम प्रशासन की लड़ाई का रूप ले चुका है। परिषद के सदस्यों का कहना है कि यदि निर्वाचित निकाय के निर्णय को इस तरह बदला जाएगा तो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा ही कमजोर होगी। मामला अब कलेक्टर के परीक्षण में है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सिर्फ एक ठेका विवाद नहीं, बल्कि निगम प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की बड़ी परीक्षा बन सकता है। अब निगाहें कलेक्टर के फैसले पर–क्या होगी निष्पक्ष जांच या फिर फाइलों में दब जाएगा मामला?

शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों का भाजयुमो भिलाई ने किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के निर्देश में भिलाई युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिन पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियो का सम्मान भिलाई जिला द्वारा विभिन्न मंडलों में किया गया आज प्रदेश का हर परिवार सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है।

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से 5500 रुपए में तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है। प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 26 लाख हितग्राही लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्मदिन के अवसर पर हितग्राहियों से संपर्क कर उनका सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल, महामंत्री विनय सेन, मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह, सोनू, अर्पित, सिद्धार्थ, चंदन यादव, आशुतोष तिवारी, रोहित चौधरी, शेखर साहू, साहिल, संदीप पाली, आशीष बोरकर एवं मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सांसद बघेल ने किया वार्ड-32 में विकास कार्यों का भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल द्वारा वार्ड क्रमांक 31 मदर टेरेसा नगर में 22 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष महेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, वार्ड 31 की पार्षद प्रियंका भोला साहू, जालंधर सिंह, भोला राम साहू, राजू और सभी वार्डवासी उपस्थित थे।

अंतर विभागीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का आयोजन 14 मार्च से

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा अंतर विभागीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला) 2026 का आयोजन दिनांक 14 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक सेल एथलेटिक्स अकादमी, सेक्टर-04 मैदान में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य संयंत्र के कमर्चारियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता एवं टीम भावना को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी नियमित एवं प्रशिक्षु कर्मचारी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम दो स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेगा। पुरुष प्रतिभागी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं 800 मीटर लंबी कूद, जेवलिन थ्रो तथा शॉटपुट में भाग ले सकते हैं वहीं महिला प्रतिभागी 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर जेवलिन थ्रो तथा शॉटपुट में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के सुचारू संचालन हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक स्पर्धा में न्यूनतम चार प्रतिभागियों की उपस्थिति आवश्यक होगी, अन्यथा संबंधित स्पर्धा को निरस्त माना जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां अपने-अपने विभाग के माध्यम से क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग के कार्यालय बोकारो हॉस्टल, सेक्टर-4 में कार्यालयीन समय पर दिनांक 13 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

सेल वालीबॉल स्पर्धा के लिए बीएसपी की टीम घोषित

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा 24 से 27 फरवरी 2026 तक दुर्गापुर में सेल वालीबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सेल कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध विभिन्न इस्पात संयंत्रों की टीमें भाग लेंगी। भिलाई इस्पात संयंत्र की वालीबॉल टीम भी प्रतियोगिता में सहभागिता कर रही है।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र की वालीबॉल टीम की औपचारिक घोषणा वॉलीबॉल क्लब के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ विभाग) विष्णु पाठक, उप महाप्रबंधक (क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ) राजेंद्र प्रसाद तथा उप प्रबंधक (क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ) अभिजीत भौमिक द्वारा की गई।

इस अवसर पर अधिकारियों ने टीम का परिचय कराते हुए चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के डी.पी. सिंह को टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है वहीं टीम के अन्य सदस्यों में भिलाई इस्पात संयंत्र से ख्वाजा अहमद, पी. मनोज, लल्लन, जी. चंदन तथा राजहरा माइंस पी.के. पाटले, लक्ष्मी नारायण, राजकुमार, एस.पी. यादव एवं देवी लाल शामिल हैं। माइंस मुख्यालय से व्यास टीम के कोच एवं मैनेजर के रूप में, खिलाड़ियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं रणनीतिक सहयोग प्रदान करेंगे। उपस्थित सभी अधिकारियों ने टीम को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता में समर्पण, अनुशासन एवं टीम भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

SIR प्रक्रिया हुई पूरी : दुर्ग जिले में 2.49 लाख नाम कटे, 31,786 नए वोटर जुड़े

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं। 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए तैयार की गई सूची के अनुसार जिले में कुल 12,35,230 मतदाता दर्ज किए गए हैं। एसआईआर से पहले जिले में 14,52,509 मतदाता पंजीकृत थे। पुनरीक्षण के दौरान 2,49,065 नाम हटाए गए, जिससे संख्या घटकर 12,03,444 रह गई। इसके बाद 31,786 नए मतदाता जोड़े गए और अंतिम सूची में कुल संख्या 12,35,230 पहुंच गई।

चार माह तक चले अभियान के बाद ड्राफ्ट प्रकाशन से फाइनल प्रकाशन तक 31,786 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 8 हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। अभियान के दौरान 1,520 बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का सत्यापन किया। कुल 14,52,509 मतदाताओं का मिलान और मैपिंग की गई तथा 12,03,444 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। छह विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट सूची की तुलना में 2.80% की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। बीएलओ द्वारा किए गए सर्वे में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम हटाए गए। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया।

1742 बीएलओ की रही अहम भूमिका

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अभियान को समय-

सीमा में पूरा करने के लिए 6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), 164 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO), 1742 बीएलओ और 3030 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए गए थे।

ऐसे जांचें अपना नाम

मतदाता जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट District Administration Durg, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, मतदाता पोर्टल और ECINET ऐप के माध्यम से अपना नाम जांच सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकता है। नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है ने 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपील की है कि वे आगामी संशोधनों में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।

विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं : अल्का बाघमार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 पुलिस लाइन क्षेत्र में प्रगति पर चल रहे सड़क डामरीकरण कार्य का महापौर अलका बाघमार ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वार्ड प्रभारी देव नारायण चंद्रकार भी उपस्थित रहे।

महापौर ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डामर की परत की मोटाई एवं निर्धारित तकनीकी मापदंडों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कारर्वाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान वार्ड प्रभारी देव नारायण चंद्रकार ने स्वयं टेप लेकर सड़क की चौड़ाई एवं डामर की परत की मोटाई की नापजोख की। मौके पर ही निर्माण कार्य की प्रगति की जांच कर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की गई। महापौर ने अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया कि कार्य केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पूर्ण किया जाए।

इस अवसर पर एमआईसी सदस्य नीलेश अग्रवाल, लोकेश्वरी ठाकुर, ललिता ठाकुर तथा उप अभियंता करण यादव भी उपस्थित रहे। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि घटिया सामग्री के उपयोग या मानक से कम मोटाई पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, कार्य पूर्ण होने तक नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए।

सड़क डामरीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद वार्ड क्रमांक 48 पुलिस लाइन क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को अब बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में चरणबद्ध तरीके से अधोसंरचना विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे दुर्ग शहर को एक व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा सके।

कुरूद बस्ती के सफाई व पेयजल व्यवस्था का आयुक्त ने किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कुरूद बस्ती में नाली सफाई व्यवस्था का निरीक्षण स्वच्छता के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

कुरूद पुरानी बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने मौके पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली एवं शंकर साहनी को सफाई व्यवस्था में निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में जलभराव या गंदगी की समस्या न हो। उन्होंने कुरूद बस्ती के पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया, और पाइपलाइन लीकेज मरम्मत हेतु निर्देशित किये हैं।

शासन की मंशा के अनुरूप, बुजुर्गों को बेहतर आश्रय और सुविधाएं प्रदान करने के लिए शासकीय भूमि का अवलोकन किया गया। यह सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तरह के औचक निरीक्षणों से न केवल निगम के कार्यों में पारदर्शिता आती है, बल्कि स्थानीय निवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित होता है। वृद्ध आश्रम के लिए भूमि का चयन यह दर्शाता है कि प्रशासन बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी समान ध्यान दे रहा है। जनहित के इन कार्यों से शहर की स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार होने की पूरी संभावना है।

सराहनीय कदम नागरिकों ने रखी अपनी समस्याएँ, सुझाव और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को किया साझा

जनसेवा, धर्म और संवेदनशीलता–इंद्रजीत सिंह 'छोटू' की कार्यशैली बनी पहचान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शहर में जनसंपर्क, सामाजिक सक्रियता और धार्मिक सहभागिता की मिसाल बन चुके हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर एवं सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह (छोटू) हर दिन की तरह आज भी कोहका स्थित सर्व समाज कल्याण समिति कार्यालय में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, वरिष्ठजनों, मातृशक्ति एवं युवाओं से आत्मीय भेंट की।

कार्यालय में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएँ, सुझाव एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को साझा किया। इंद्रजीत सिंह ने प्रत्येक विषय को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी आयोजनों के आमंत्रण भी प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए आयोजकों को सफल एवं मंगलमय आयोजन की शुभकामनाएँ दीं।

विवेकानंद नगर, कोहका स्थित आनंदेश्वर महादेव हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर आनंदेश्वर महादेव हनुमान जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित रुद्राभिषेक पूजन एवं महाभंडारा प्रसादी कार्यक्रम में भी इंद्रजीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, सर्व समाज कल्याण समिति के महासचिव शमलकीत सिंह जी, इंद्रजीत सिंह चिंटू जी, रणजीत सिंह जी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मंदिर निरीक्षण कर दिया सहयोग का आश्वासन

क्षेत्रवासियों की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई स्थित शिव हनुमान एवं दुर्गा मंदिर पहुँचकर उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर की छत एवं गुंबद से हो रहे पानी के रिसाव की समस्या से समिति एवं कॉलोनीवासियों ने उन्हें अवगत कराया। इस संबंध में उन्होंने यथासंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण

कैलाशनगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई स्थित प्रीत पैलेस में यूथ सिख सेवा समिति के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के भाई स्व. सरदार शोभा सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी इंद्रजीत सिंह छोटू सम्मिलित हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर परिवारजनों द्वारा दो दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई तथा एक ट्राईसाइकिल समाजसेवा हेतु सर्व समाज कल्याण समिति को सहयोग स्वरूप भेंट की गई। इंद्रजीत सिंह ने स्वर्गीय सरदार शोभा सिंह जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु से प्राथर्ना की तथा इस पुनीत कार्य के लिए परिवारजनों का आभार व्यक्त किया।

जनता से सीधा जुड़ाव ही पहचान

उल्लेखनीय है कि इंद्रजीत सिंह छोटू की कायर्शैली का मूल आधार जनता से सीधा संवाद और त्वरित सहयोग है। सामाजिक, धार्मिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहकर वे समाज के हर वर्ग से आत्मीय संबंध बनाए हुए हैं। यही कारण है कि शहर में वे केवल एक पदाधिकारी नहीं, बल्कि जनभावनाओं से जुड़े जनसेवक के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

बीएमडीसी में आईएसओ मानकों पर आधारित चार दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के व्यावसायिक उत्कृष्टता विभाग द्वारा संयंत्र के विभिन्न विभागों में नवीन आंतरिक लेखा परीक्षकों के विकास हेतु 17 से 20 फरवरी 2026 तक बीएमडीसी, सेक्टर-7, भिलाई में चार दिवसीय आईएमएस (इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम) आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के अंतर्गत ऑडिट आवश्यकताओं की व्यावहारिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) ढांचे के अनुरूप प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सक्षम बनाना था।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 25 अधिकारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण सत्र का संचालन मेसर्स टीयूवी इंडिया प्रा. लि. के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ श्री शलभ कपूर द्वारा किया गया, जिन्हें लेखा परीक्षा एवं प्रशिक्षण में लगभग 50 वर्षों का समृद्ध व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है।

प्रशिक्षण सत्र के सफल समापन उपरांत प्रतिभागियों को मेसर्स टीयूवी इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्रमाणित आईएमएस आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष शिवराजन ने उद्बोधन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रबंधन प्रणालियों की गहन समझ, बेहतर अनुपालन, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा व्यावसायिक विकास जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। उद्घाटन सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक रवि कुमार द्वारा तथा आभार प्रदर्शन महाप्रबंधक सुरैया एस. कादर ने किया।

उपभोक्ता न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण पहल

खाद्य मंत्री बघेल ने उपभोक्ता संरक्षण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने उपभोक्ता संरक्षण विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कायर्शाला में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी साही, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, मध्यप्रदेश, गोवा, बिहार, झारखंड उत्तरप्रदेश सहित आठ राज्यों के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी साही ने कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी एवं विधिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में जागरूकता एवं तकनीकी पहलुओं की प्रशिक्षण के लिए कायर्शाला का आयोजन किया जा रहा है। कायर्शाला में तकनीकी, डिजिटल व्यवस्था, प्रक्रियात्मक सुधार और विधायी संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान दौरान ई-प्रणालियों का विस्तार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग की जानकारी दी गई। वहीं ई-जागृति, ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग जैसी डिजिटल सुविधाओं के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को घर बैठे शिकायत दर्ज करने और सुनवाई में भाग लेने की सुविधा मिल रही है। उपभोक्ता न्याय को किफायती, पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान शिकायत स्वीकृति की प्रक्रिया, उपभोक्ता आयोग के आर्थिक एवं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, शिकायत और जवाब दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को स्पष्ट किया। इस दौरान यह भी बताया गया कि यदि प्रतिवादी पक्ष 30 दिनों की निर्धारित अवधि या अधिकतम 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि (कुल 45 दिन) में लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके साक्ष्यों पर विचार सीमित हो सकता है। साथ ही प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के गवाहों से जिरह का अवसर और उसकी सीमा पर भी चर्चा हुई।

अधिकारियों एवं न्यायमूर्तियों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ती चुनौतियों, डार्क पैटर्न जैसी भ्रामक डिजाइन तकनीकों और झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दों पर चर्चा की। क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों और तकनीकी जटिलताओं के त्वरित समाधान हेतु वर्तमान संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। निष्पादन आवेदन के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों और प्रणालीगत विलंब संबंधी जानकारी दी गई।

सभी उपभोक्ता आयोगों में प्रक्रियात्मक एकरूपता लाने, मानकीकृत नियम एवं दिशानिर्देश अपनाने तथा केस मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने पर भी जोर दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खास खबर

26 से 28 फरवरी तक तीन दिवसीय आयुष्मान कार्ड महाअभियान शिविर का होगा आयोजन'

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आयुष्मान कार्ड महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार व जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के.डी. पैकरा के मार्गदर्शन में 26 से 28 फरवरी तक तीन दिवसीय आयुष्मान कार्ड महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा स्वास्थ्य दल पारा, मोहल्ला एवं घर-घर जाकर वंचित हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रह सके।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि सामान्य राशन कार्डधारी हितग्राहियों को 50 हजार रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की विशेष सुविधा दी जाती है।

अब तक जिले में कुल राशन कार्डधारियों के विरुद्ध 93 प्रतिशत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, वहीं 84 प्रतिशत वय वंदना कार्ड का निर्माण किया जा चुका है। शेष वंचित हितग्राहियों को इस महाअभियान के माध्यम से योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन ने समस्त पात्र एवं आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस महाअभियान का लाभ उठाएं और 26 से 28 फरवरी के बीच नजदीकी शिविर में पहुंचकर अथवा घर पर ही अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, क्योंकि यह कार्ड किसी भी गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है।

मंत्री रामविचार नेताम का कृषि विश्वविद्यालय किया निरीक्षण

राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसंधान आधारित कृषि नवाचारों को बढ़ावा देना है

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रक्षेत्र एवं विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रहे उन्नत कृषि अनुसंधान, बीज विकास, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने शोध गतिविधियों, प्रयोगात्मक परियोजनाओं और किसानों के हित में विकसित की जा रही तकनीकों की जानकारी ली। उन्होंने वैज्ञानिकों और प्राध्यापकों से संवाद करते हुए अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता, जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री ने विशेष रूप से बीज विकास और प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुसंधान को प्रदेश के कृषि परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसंधान आधारित कृषि नवाचारों को बढ़ावा देना है।

ताकि प्रदेश के किसानों को नई तकनीकों और उन्नत पद्धतियों का लाभ मिल सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और अधिक आय अर्जित करने योग्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित अन्य वरिष्ठ प्राध्यापक एवं शोधकर्ता उपस्थित रहे। कुलपति ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यों, नवाचार परियोजनाओं और किसानों के लिए विकसित तकनीकों की जानकारी मंत्री को दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, टिकाऊ खेती पद्धतियों और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुसंधान कार्यों के परिणामों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाए। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जल संरक्षण से जुड़े शोध कार्यों को और गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निरीक्षण प्रदेश में कृषि विकास और अनुसंधान को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों को उन्नत तकनीक और नवाचारों का लाभ दिलाने के लिए सरकार और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

27 दिनों तक चिकित्सकों की देखभाल से नन्हीं जान को मिला नया जीवन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी विजन के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे अब जिला मुख्यालयों पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रहे हैं। इसी का जीवंत उदाहरण जिला अस्पताल कोंडागांव की नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एसएनसीयू) में देखने को मिला, जहां एक गंभीर नवजात शिशु को नया जीवन मिला है।

कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के सतत निर्देशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रेमलाल मंडावी के नेतृत्व में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया जा रहा है। आवश्यक संसाधनों, जीवन रक्षक उपकरणों एवं दवाइयों की उपलब्धता तथा नियमित मॉनिटरिंग के कारण आज एसएनसीयू दूरस्थ अंचलों के लिए आशा की किरण बन चुकी है।

ग्राम राकसबेड़ा, विकासखंड माकड़ी निवासी बो सुखदई मरकाम एवं चैतराम मरकाम के नवजात शिशु का जन्म 18 दिसंबर 2025 को शाम 5:28 बजे हुआ। जन्म के तुरंत बाद शिशु की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। 20 दिसंबर 2025 को शिशु को एसएनसीयू में भर्ती किया गया। जन्म के समय शिशु का वजन 2.70 किलोग्राम था तथा वह बर्थ एस्फिक्सिया, लगातार दौरे और संक्रमण जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा था। गर्भावस्था के दौरान माता में गंभीर ओलिगोहाइड्राम्नियोस की स्थिति भी पाई गई थी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रुद्र कश्यप, डॉ. राजेश बघेल एवं डॉ. परोमिता सूत्रधार सहित एसएनसीयू की टीम ने शिशु का तत्काल उपचार प्रारंभ किया। प्रारंभिक दिनों में ऑक्सीजन सपोर्ट एवं एंटीबायोटिक दिए गए, परंतु अपेक्षित सुधार न होने पर पांचवें दिन शिशु को मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया, जहां 12 दिनों तक गहन निगरानी में उपचार जारी रहा। उपचार के दौरान शिशु में सेप्सिस एवं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जैसी जटिलताओं की पहचान हुई।

खेल के मैदान से मिलता है स्वास्थ्य, समन्वय और सफलता का मंत्र : अरुण साव

पत्रकार खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा सुभाष स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति इंटर-प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचकर पत्रकार खिलाड़ियों से आत्मीय मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेल मड़ई के सफल आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब और पत्रकारों को बधाई दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने फाइनल मैच खेल रही संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक टीम के कप्तान एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी तथा विस्तार न्यूज टीम के कप्तान मृगेंद्र पांडेय सहित दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक टीम ने विस्तार न्यूज को पराजित कर खिताब अपने नाम किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुभाष स्टेडियम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल का मैदान व्यक्ति को जीवन की अनमोल पूंजी प्रदान करता है। खेल हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छे दोस्त देता है, समन्वय की भावना सिखाता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति को यह सब मिलता है तो वह जीवन में प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है और निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर होता है। श्री साव ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पिछले कई दिनों से आयोजित इस खेल मड़ई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी स्नेह को बढ़ाते हैं और स्वस्थ जीवन-शैली के लिए प्रेरित करते हैं। पत्रकारिता जैसे दायित्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय साथियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार साथी इसी तरह मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते रहें।

उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन पुल के कार्य का किया निरीक्षण

धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अपने लोरमी प्रवास के दौरान ग्राम कारीडोंगरी और दरवाजा के मध्य मनियारी नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को बरसात से पहले हर हाल में पुल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कार्य पूणर्ता के लिए निर्धारित लक्ष्य से बहुत धीमा काम चलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल का काम अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। श्री साव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार पर पेनाल्टी भी लगाएं। निर्माण में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी, गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पुल के काम की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने साइट पर मजदूरों की संख्या बढ़ाने और निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा, ताकि बरसात के पहले पुल आवागमन के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना है, इसे समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करना शासन की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मनियारी नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में वनांचल क्षेत्र के अनेक गांवों का संपर्क टूट जाता है। इससे लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और दैनिक आवश्यकताओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पुल के बन जाने से कारीडोंगरी, दरवाजा सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

'सीखो-सिखाओ, अंजोर फैलाओ' कार्य संस्कृति के जरिए विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने किया जा रहा तैयार

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट संकल्प-2026 का राज्यव्यापी क्रियान्वयन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट संकल्प के तहत वर्ष 2026 के लिए दो चरणो में विभागीय अधिकारियों और अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी आश्रम-छात्रावासों में प्रोजेक्ट संकल्प का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य सीखो-सिखाओ, अंजोर फैलाओ की कार्य संस्कृति को संस्थागत स्वरूप देना तथा विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए तैयार करना है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा है कि छात्रावास केवल आवासीय सुविधा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व विकास के सशक्त मंच हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लिया जाए, ताकि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो चरणों में संपन्न होगा

प्रथम चरण में जनजाति बाहुल्य 21 जिलों के सहायक आयुक्तों का 2.5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में जीवन के रंग, खुशियों के संग कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिलों में कार्यान्वयन की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत सभी जिलों द्वारा अपने-अपने छात्रावासों के लिए काययोजना विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

द्वितीय चरण में छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षकों के लिए 8 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 6 दिनों तक प्रतिदिन 3 घंटे के सत्रों में सफलता मंत्र 1 से 9 तक की अवधारणाएँ साझा की जाएंगी। बीच के दो दिनों में अधीक्षक सीखी हुई बातों को अपने जीवन एवं विद्यार्थियों के साथ व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार तैयार अधीक्षक छात्रावासों में विद्यार्थियों, सहयोगियों तथा जहाँ संभव हो अभिभावकों के साथ भी प्रशिक्षण की सीख साझा करेंगे, जिससे सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण का निर्माण हो सके।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि प्रोजेक्ट संकल्प-2026 के माध्यम से राज्य के छात्रावासों एवं आश्रमों में नई कार्य संस्कृति की स्थापना कर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, अनुशासित एवं सफल नागरिक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। इस पहल से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ नैतिक सामाजिक एवं जीवन कौशल से भी सशक्त बनाया जा रहा है। आश्रम-छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित शैक्षणिक सहयोग तथा खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छात्रावासी बच्चों के भविष्य को नई उड़ान देने के उद्देश्य से यह अभिनव पहल की गई हैं।

सीए साय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का किया आत्मीय स्वागत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूयर्कांत के छत्तीसगढ़ आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक स्वरूप राजकीय गमछा, विश्वविख्यात बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक तथा बेल मेटल से निर्मित भगवान श्रीराम एवं माता शबरी की आकर्षक प्रतिकृति भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उल्लेखनीय है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूयर्कांत हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (Hidayatullah National Law University) के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने हेतु छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं।

संपादकीय

खाते में नगद पैसा किसको बुरा लगता है

कहावत है कि घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है। घर आई लक्ष्मी का तो हर कोई स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी घर आनी चाहिए। जनता के खाते जितना नगद पैसा आता है उसको भी उतना ही अच्छा लगता है। अब तो अच्छी सरकार वही मानी जाती है जो जनता की जेब में ज्यादा नगद पैसा डालती है। वह जमाना गया जब सरकार जनता को योजना बनाकर फायदा पहुंचाया करती है। अब तो डिजिटल युग है,दिल्ली से या राज्य की राजधानी से नगद पैसा डालो और वह सीधे जनता के खाते में पहुंच जाता है। खाते मे पैसा आता है जनता को अच्छा लगता है, सरकार को भी यह बताते हुए अच्छा लगता है कि उसने कितने महिलाओं के खाते में कितना पैसा डाला है। किसानों के खाते में कितना पैसा डाला है,मजदूरों के खाते में कितना पैसा डाला है।सरकार हर महीने पैसा जनता के खातों में डालती रहती है और अच्छी सरकार बनी रहती है।

जो दल सत्ता में है वह इसलिए पैसा खातों में डालता रहता है कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था।जनता ने उनके वादे पर यकीन कर सत्ता सौंपी है तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा। वादा पूरा नहीं किया नहीं किया को अगली बार जनता सत्ता से बाहर कर देगी। एक बार सत्ता में आने के बाद कोई राजनीतिक दल सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहता है इसलिए जो सत्ता में हैं, वह सत्ता में रहने के लिए जनता को पैसा देते रहते हैं और जो लोग सत्ता में फिर से आना चाहते हैं वह चुनाव के पहले जनता से फिर वादा करते हैं कि वह सत्ता में आए तो और कितना पैसा जनता के खाते में डालेंगे।तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार है, वह सत्ता में रहते तो जनता के खाते में सहायता के नाम पर पैसा डाल रही है।

इसी साल चुनाव है फिर से सत्ता में आना है इसलिए मंत्री ने चुनाव के पहले महिलाओं को बता दिया कि सरकार ने उनके खाते में एकमुश्त पांच हजार रुपए डाल दिए हैं। इसमें तीन हजार रुपए तीन माह की मासिक सहायता है और दो हजार रुपए ग्रीष्मकालीन विशेष पैकेज के रूप में दिया गया है। पं.बंगाल में सरकार युवाओं को युवा साथी नगद योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को 1500 रुपए देने की योजना बनाई है। बिहार में सरकार ने इसी तरह महिलाओं के खाते में एक मुश्त दस हजार रुपए चुनाव के पहले डाले थे तो कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया था।अब विपक्ष शासित राज्य तमिलनाडु व पं. बंगाल में वही किया जा रहा है तो विपक्ष के किसी नेता यह बुरा नहीं लग रहा है।

जनता को नगद पैसा देना राजनीतिक दलों को बुरा नहीं लगता है हर राजनीतिक मानता है कि सत्ता हासिल करनी है तो जनता को नगद पैसा देना होगा। जनता को नगद पैसा देने पर ही चुनाव में जीत मिलती है। कई राज्यों में राजनीतिक दलों को जीत मिली है इसलिए जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए जनता से नगद पैसा देने का वादा कर रहे हैं।तमिलनाडु सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जिसमें राज्य सरकार जनता को चुनाव के पहले मुफ्त बिजली देना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाई है कि इस तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहेंगे तो विकास के लिए पैसा कहां से बचेगा।सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को याद दिलाया है कि देश के ज्यादातर राज्य तो पहले से घाटे में है। फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं और नगद पैसे बांट रहे हैं।जो लोग भुगतान नहीं कर सकते उन्हें सहायता देना समझ मे आता है लेकिन अमीर गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त सुविधा देने गलत नीति है।

यह बात तो राजनीतिक दल भी जानते हैं लेकिन उनको चुनाव के पहले सबका वोट चाहिए इसलिए वह सबको देने का वादा करते हैं, चुनाव के बाद वह नियम व शर्ते लगाकर लोगों की संख्या कम करने का प्रयास करते हैं। .ऐसा कई राज्यों में हो चुका है। फिर भी जिन लोगों को नगद पैसा मिलता है, उनकी संख्या लाखों से लेकर एक दो करोड़ तो होती ही है। यह सच है कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होता है लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद खूब भ्रष्टाचार करते है अपने लिए, परिवार के लिए और पार्टी के लिए भी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है तो लगाते रहे राजनीतिक दलों को पहले इस तरह की फटकार का कोई असर हुआ है और न भविष्य में होने वाला है।

प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व गढ़ रहा है विकास के नए सोपान

छगन लाल लोन्हारे
उपसंचालक जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सह्रदयता की एक मिसाल है। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़ने वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान है। विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं।

केबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होंगे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी।

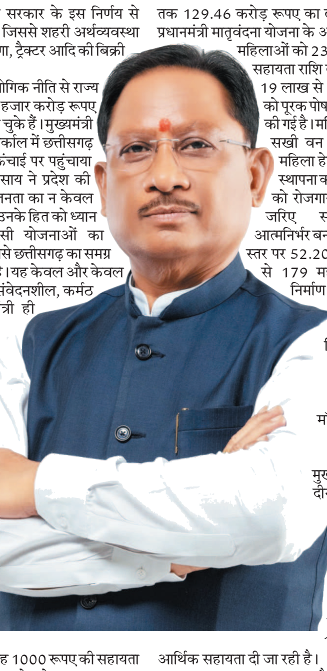

प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं।

विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व- सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-विशाखापट्नम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है।

मुख्यमंत्री श्री साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निः स्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, समर्पित और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा हो तो विकास की राह कठिन नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम

अजीत द्विवेदी

वैसे तो अप्रैल में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है। और ऐसा होने के कई कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का चुनाव कम महत्वपूर्ण है या केरल और असम का चुनाव ज्यादा महत्व का नहीं है। असम और केरल का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन मरण का चुनाव है तो तमिलनाडु डीएमके, अन्ना डीएमके और फिल्म स्टार विजय के लिए बहुत अहम है। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर जिस चुनाव का सबसे ज्यादा असर होगा वह पश्चिम बंगाल का है। अगर ममता बनर्जी लगातार चौथी बार चुनाव जीतती हैं तो सिर्फ बंगाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी और सिर्फ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए पर ही नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियाइ की राजनीति पर भी बड़ा असर होगा।

चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह अकेले सभी 294 सीटों पर लड़ेगी। दूसरी ओर वामपंथी पार्टियों का मोर्चा भी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा है। 2016 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। पिछले दो चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच सीट एडजस्टमेंट की सहमति बनी थी और दोनों ने मिल कर चुनाव लड़ा था। पिछली बार यानी 2021 में तो फुरफुराशरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ भी सीटों का समझौता हुआ था। इस बार देखने वाली बात होगी कि आईएसएफ की कमान संभाल रहे नौशाद सिद्दीकी क्या फैसला करते हैं। उनका फैसला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम गठजोड़ के अलग से चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। तृणमूल से चुनाव जीते हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाई है।

वे मुशिर्दाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और मुस्लिम ध्रुवीकरण के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक सभा की तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इरफान सोलंकी भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर इस बार ओवैसी की पार्टी एमआईएम और बदरूद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीफ से तालमेल करेंगे। अगर आईएसएफ इसमें शामिल हो तो चार मुस्लिम पार्टियों का एक मोर्चा बनेगा। हालांकि इस बीच यह भी खबर है कि सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी हुमायूं कबीर से मुलाकात की है। तो क्या लेफ्ट मोर्चा इन मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकता है? जो हो अभी तक यह दिख रहा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस, लेफ्ट और मुस्लिम पार्टियों के मोर्चे की चुनौती है। दूर से एक बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं।

चुनाव से पहले बन रहे गठबंधनों की पृष्ठभूमि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटों के बंटवारे या ध्रुवीकरण से चुनावी नतीजे तय होते हैं। लगभग 30 फीसदी मुस्लिम आबादी लगभग पूरी तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थन में वोट करती है। दूसरी ओर 70 फीसदी हिंदू आबादी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा भाजपा का समर्थन करता है।इसका अर्थ है कि अगर 10 फीसदी और हिंदू वोट भाजपा के साथ जुड़ जाएं तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी या अगर 20 फीसदी के करीब मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से टूट जाए तब भी भाजपा जीत जाएगी। भाजपा का 38 से 40 फीसदी तक वोट कायम रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि पिछले तीन चुनावों में उसे इतना ही वोट मिलता है और उसे इसे और कंसोलिडेट किया है।

पिछले चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ को साझा तौर पर 12 फीसदी के करीब वोट मिला था। इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा हिंदू वोट का था। ध्यान रहे बांग्ला बोलने वाला हिंदू समुदाय भाजपा के साथ जाने की बजाय ममता बनर्जी या लेफ्ट, कांग्रेस के साथ रहता है। लेकिन इस बार स्थिति बदलने की संभावना है। बांग्लाभाषी हिंदू पहली बार मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि भाषा और संस्कृति की एकता बनाने के चक्कर में बांग्लाभाषी हिंदू पहले कांग्रेस फिर लेफ्ट और अब तृणमूल को वोट देते रहे हैं लेकिन इस बीच राज्य की जनसंख्या संरचना बदल गई और उनके सामने गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं। अगर बांग्लाभाषी हिंदू इस मानसिकता में वोट करते हैं तो भाजपा के लिए अवसर बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू ध्रुवीकरण मजबूत होगा।

अगर चुनिंदा इलाकों में जैसे मालदा, मुशिर्दाबाद और उत्तरी दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर मुस्लिम आवाम का समर्थन मुस्लिम नेताओं की पार्टियों को मिलता है तो हैदराबाद से शुरू होकर महाराष्ट्र और बिहार तक मुस्लिम नेतृत्व के प्रति मुस्लिम आवाम के बढ़ते रूझान पर मुहर लगेगी। यह ट्रेंड स्थायी रूप से देश की राजनीति को बदलने वाला होगा। ध्यान रहे बिहार में आमने सामने के चुनाव के बावजूद ओवैसी की पार्टी के पांच विधायक जीते।

ऑपरेशन भी होगा तो शर्तों के साथ

हरिशंकर व्यास

तो आज का वक्त भारत का सेनापति बेचारा (थलसेना प्रमुख-जनरल एमएम नरवणे) 'सबसे ऊपर से'.. आदेश की प्रतीक्षा के अनुभव वाला। अंत में जवाब - जो उचित समझो, वह करो। कितनी गंभीर बात। तभी विचार करें नेहरू के बनाए भारत और जिन्ना के बनाए पाकिस्तान में क्या फर्क है? नेहरू की जिद्द थी कि सिविल सरकार से सेना आदेश लेगी। जबकि जिन्ना ने दिमाग नहीं लगाया। नतीजतन पाकिस्तान में रिवाज है सेना देगी सिविल सरकार को आदेश। वह चलाएगी सरकार!

इस फर्क को क्या नरेंद्र मोदी, अजित डोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर या संघ परिवार के लाठीधारी जानते हैं? चलिए आज आपको राहुल गांधी के पुरखे जवाहरलाल नेहरू की समझ का एक प्रमाण दें। वह सबूत, जिससे पाकिस्तान में सैनिक सर्वशक्तिमान है वही लोकतांत्रिक भारत भयाकुल सिविलियन नरेंद्र मोदी से शासित है।

नेहरू आजादी से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वायसराय की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे। वह कार्यकारिणी देश के प्रशासन का बिंदु थी। उसमें ब्रितानी सेना के प्रमुख की सदस्यता अनिवार्य थी। पर नेहरू ज्योंहि उपाध्यक्ष बने उनका निर्णय था नागरिक व्यवस्था, राजनीतिक निणर्यो की बैठकों में सेना प्रमुख का क्या काम! वह सदस्य नहीं होगा। उन्होंने वायसराय कार्यकारिणी में सेना प्रमुख को सदस्य नहीं बनाने की अनुशंसा की। नेहरू ने साफ स्टैंड लिया कि शासन-प्रशासन से सेना को दूर रखा जाना चाहिए, ताकि सत्ता का संतुलन नागरिक नेतृत्व के अधीन रहे। तब नेहरू और कांग्रेस नेताओं को बोध था कि भारत में विदेशी शासन सैन्य छावनियों के बल पर था। सो, भविष्य के लोकतांत्रिक भारत में सेना को शासन से दूर रखने का निर्णय हुआ।

और नेहरू ने वायसराय कार्यकारिणी में सेना प्रमुख के स्थान पर सेना के प्रतिनिधि मंत्री के रूप में नेता सरदार बलदेव सिंह को कायर्कारिणी का सदस्य बनाया। फिर वह हरसंभव प्रयास किया, जिससे सेनाध्यक्ष की प्रशासनिक मामलों से दूरी बनी। वह हस्तक्षेप न हो और न ही नीतिगत निणर्यो में निर्णयकर्ता या भागीदार बने। लोकतंत्र को स्थिर, टिकाऊ बनाए रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया। इसी से नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच एक संस्थागत संतुलन स्थापित हुआ। इसके अलावा, नेहरू ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के कायर्काल को निश्चित अवधि का बनाया, जिससे सैन्य पदों पर अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव को रोका जा सके। सेवानिवृत्त सेना प्रमुखों, जैसे जनरल करियप्पा, को दूरस्थ देशों में राजदूत नियुक्त किया। मतलब सैन्य नेतृत्व की राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखने की परंपरा बनाई। खुफिया एजेंसियों के माध्यम से निगरानी तंत्र विकसित किया।

तभी नेहरू से मोदी के सत्ता में आने तक हर सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग-अलग रखे। चीन के हमले के बाद तीनों सेना के कमान से ऊपर एक प्रमुख की नियुक्ति की सलाह दी जाती रही। लेकिन भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने नेहरू की इस समझ को अपनाए रखा कि एक शक्तिशाली सैन्य पद लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। उस सोच-सावधानी को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस) बना कर और सन् 2020 में जनरल रावत को नियुक्त कर खत्म किया। शायद इसलिए क्योंकि गुजरात से आए नरेंद्र मोदी ने अपनी कमी (सीधे बात करने, निर्देश देने, कैबिनेट में रियल विचार विमर्श निर्णय की क्षमता, विश्वास में कमी) को ढकने के लिए सीएमओ के ढर्रे पर खास-विश्वस्त एनएसए अजित डोवाल, पीएमओ के प्रमुख सचिव, विश्वस्त अमित शाह की कमांड बनाई तो सेना के लिए भी एक विश्वस्त की जरूरत थी। सो, वे बतौर सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल (आईपीएस अफसर) को मन की बात कहें। उसे डोवाल सेनाध्यक्ष, सीडीएस को सुनाए और सीडीएस फिर थल, वायु, नौ सेना के प्रमुखों को हुकूम दे। इस कमांड चेन के अनुभव पुलवामा, गलवान, डोकलाम, ऑपरेशन सिंदूर में झलके हैं। वैश्विक तौर पर भारत की सैन्य क्षमता पोली हुई मानी गई है।

सो, नेहरू ने भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देने के लिए निर्वाचित सरकार को सर्वेसर्वा बनाया। मगर हां, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी होगा, जिसमें न तो कैबिनेट बैठक, कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी में खुले मंथन की हिम्मत होगी। न सीधा आदेश मिलेगा। और ऑपरेशन भी होगा तो शर्तों के साथ। फिर भले सीमा की तरफ चीनी सैनिक, टैंक बढ़ रहे हैं तो सेनाधिकारियों के संग नफे-नुकसान पर विचार के बिना रक्षा मंत्री के जरिए अंत में संदेश भिजवा देंगे, जो उचित समझो, वह करो।

आरक्षण की व्यवस्था जस की तस

अजीत द्विवेदी

लोक कल्याण या एफर्मेटिव एक्शन से जुड़े हर कानून में या हर नीतिगत फैसले में एक 'एक्जिट क्लॉज' या 'सनसेट क्लॉज' होता है। यह इसलिए जरूरी होता है ताकि जब कानून का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सके। हालांकि भारत में ऐसा होता नहीं है। संविधान बनाने वालों ने आरक्षण को 10 साल और अंग्रेजी को 15 साल तक कामकाज की भाषा रखने का कानून बनाया था। लेकिन आजादी के 77 साल बाद तक दोनों चीजें बनी हुई हैं। आजादी के 77 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था न सिर्फ जस की तस चल रही है, बल्कि उसमें नए नए किस्म के आरक्षण जुड़ रहे हैं। आरक्षण बढ़ाने और उसके दायरे का विस्तार करने की मांग भी उठ रही है और हैरानी नहीं होगी, अगर अगले साल होने वाली जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाया जाए और उसके दायरे में निजी क्षेत्र और उन सभी क्षेत्रों को भी लाया जाए, जो अभी उसके दायरे से बाहर हैं।

'मुफ्त की रेवड़ी' का मामला भी आरक्षण की व्यवस्था की तरह होता जा रहा है। कोई भी लोक लुभावन घोषणा ऐसी ही होती है। वह शेर की सवारी की तरह है। उस पर सवारी तो सर्वशक्तिमान होने का अहसास कराती है लेकिन यह खतरा हमेशा रहता है कि उस पर से गिरे तो शेर खा जाएगा। इसी चिंता में कोई भी पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने के बारे में नहीं सोचती है, उलटे आगे बढ़ कर श्रेय लेती है कि उसने आरक्षण में और क्या क्या जोड़ दिया। इसी तरह इन दिनों 'मुफ्त की रेवड़ीइ का मामला है। भले ही अर्थव्यवस्था का रक्तस्त्राव बढ़ता जा रहा है और हालत बिगड़ती जा रही है लेकिन कोई इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उलटे सभी राज्य हर चुनाल से पहले नकद बांटने की कोई न कोई नई योजना घोषित कर रहे हैं।

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश किया तो महिलाओं के मिलने वाली मासिक आर्थिक मदद को एक हजार रुपए से बढ़ा कर डेढ़ हजार कर दिया। साथ ही बेरोजगार युवाओं को डेढ़ हजार रुपया महीना देने की घोषणा की। बजट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो 15 अगस्त 2026 से युवाओं को डेढ़ हजार रुपया महीना दिया जाएगा। लेकिन उनको लगा कि अगस्त से देने का वादा शायद ज्यादा वोट नहीं दिला सके तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव से पहले ही बेरोजगारों को यह पैसा मिलने लगेगा। पश्चिम बंगाल सरकार एक अप्रैल से युवाओं को डेढ़ हजार रुपया महीना देगी। ध्यान रहे अप्रैल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है इसका मकसद चुनाव को प्रभावित करना है। बिहार में इसी तरह चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत हर घर की एक महिला को 10 हजार रुपए देना शुरू किया। झारखंड में मइया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार दूसरी बार जीतने में मदद की। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से राजधानी दिल्ली तक किसी न किसी रूप में एक से ज्यादा 'मुफ्त की रेवड़ीइ वाली योजनाएं चल रही हैं।

इस साल आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सर्वे पेश किया उसमें 'मुफ्त की रेवड़ीइ बांटने वाली योजनाओं को लेकर चिंता जताई गई। कहा गया कि इससे लोगों को तत्काल फायदा तो होता है लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान हो रहा है। फायदे का तो पता नहीं है लेकिन नुकसान को लेकर कई आंकड़े पहले भी सामने आ चुके हैं। महिला को नकद रुपए देने की योजना पर राज्यों का कुल खर्च सालाना दो लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कई सर्वेक्षणों में बताया गया कि नकद पैसे और मुफ्त की वस्तुओं और सेवाओं की वजह से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो रही है। महाराष्ट्र में माझी लड़की बहिन योजना के बाद महिलाओं की कामकाज में भागीदारी कम होने की खबर आई थी।

ध्यान रहे देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम ही हैं और असंगठित क्षेत्र में रोजगार बहुत मुश्किल भी है और श्रमसाध्य भी है। सरकारें उसे ठीक नहीं कर पा रही हैं। इस बीच लोगों को नकद पैसे मिल रहे हैं और मुफ्त में सेवाएं व वस्तुएं भी मिल रही हैं, जिससे बहुत आरामदेह तो नहीं लेकिन जीवन जीने की स्थितियां मिल रही हैं। इसका असर उत्पादकता पर पड़ रहा है। भारत को इस समय मुफ्त की वस्तुएं, सेवाएं और नकद बांटने की बजाय श्रम शक्ति के सार्थक इस्तेमाल की नीतियां बनाने की जरुरत है। लोगों को सम्माननजक रोजगार और वेतन मिले इसके उपाय करने की जरुरत है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यूरोपीय संघ से लेकर अमेरिका तक के साथ भारत की व्यापार संधि हो रही है और भारत के उत्पादों के लिए दुनिया का बाजार खुल रहा है। अगर भारत में विनिर्माण सेक्टर मजबूत होता है और कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है तो करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन संवारना आसान हो जाएगा।

इसकी बजाय अगर भारत में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन जारी रहता है तो इन बदली हुई स्थितियों का लाभ उठाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही राज्यों की हालत और बिगड़ती जाएगी। उनका खर्च और कर्ज दोनों बढ़ेगा। जैसे जैसे कर्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ब्याज चुकाने में ज्यादा रकम खर्च होगी। इससे लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य का खर्च कम होगा और बुनियादी ढांचे के विकास का खर्च भी कम होगा। राज्यों की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से कई राज्यों में सरकारों ने इस बारे में सोचना शुरू किया है। लेकिन वही शेर की सवारी वाली बात है इसलिए कोई अपनी तरफ से आगे बढ़ कर ऐसी योजनाओं को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है।

लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार के लिए पहुंचा है और चीफ जस्टिस ने इस पर विचार के लिए तीन जजों की बेंच का गठन कर दिया है। कायदे से पहले ही पांच जजों की बेंच बना कर संविधान पीठ में ही सुनवाई होती तो बेहतर होता। लेकिन तीन जजों की बेंच भी लोक कल्याण को परिभाषित कर सकती है और 'मुफ्त की रेवड़ीइ व लोक कल्याण का फर्क समझा जा सकती है। ज्यादातर राज्य सरकारें चाहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग दे तो वे उसको लागू करें और नकद पैसे बांटने या सेवाएं व वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजनाओं को बंद करें। ध्यान रहे इस देश में बहुत सारे अलोकप्रिय या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को अदालत के फैसलों से सुलझाया गया है। 'मुफ्त की रेवड़ीइ का मामला भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा तो केंद्र से लेकर राज्यों तक को नोटिस भेजा जाएगा या खुद राज्य सरकारें पक्षकार बनेंगी। ध्यान रहे मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य से लेकर बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों आदि के लिए जन कल्याण की योजनाएं पहले भी चलती थीं। उन्हें किस रूप में जारी रखना है यह अदालत को तय करना है। लोक कल्याण और 'मुफ्त की रेवड़ी' का फर्क साफ साफ बताना होगा ताकि बाद में सरकारें चुनावी फायदे के लिए सरकारी खजाना लुटाने वाले काम नहीं कर सकें और साथ ही जरुरतमंदों को मदद भी मिलती रहे। महिलाओं को पैसे बांट कर बिहार चुनाव जीतने के आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका तो खारिज हो गई लेकिन अदालत ने कहा कि वह इस मामले को देख रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च अदालत से कोई स्पष्ट आदेश आएगा।

नालंदा परिसर से जिले को मिलेगा शैक्षणिक सशक्तिकरण–विक्रांत सिंह

4 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का हुआ भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

जिले में 4 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन समारोह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह उपस्थित रहे। विधि-विधान के साथ पूजा-अचर्ना कर भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रांत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला के लिए नालंदा परिसर की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो जिले के शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री अरुण साव तथा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के समग्र विकास के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों एवं जनहित योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। नालंदा परिसर के निर्माण से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू, टीके चंदेल, गिरजा चंद्राकर, नीलिमा गोस्वामी, देवीन बाई कोठले, मोनिका रजक, शशांक ताम्रकार, नंद चंद्राकर, गोरेलाल वर्मा, कीर्ति वर्मा, विनय देवांगन, रूपेंद्र रजक, हर्ष वर्मा, अनुज देवांगन, आलोक श्रीवास, हरप्रसाद वर्मा, केशव चंदेल, प्रेमसागर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

खास खबर

सरकार की निरंकुशता और प्रशासनिक लचरता से अपराध को बढ़ावा– रूपेश दुबे

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने सरकार की निरंकुशता और विभागों में फर्जीवाड़ा और अवैध कार्यों की लंबी फेरहिस्त को प्रमाण सहित रेखांकित करते हुए कहा कि छ ग सहित राजनांदगांव में जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र अपने सक्रिय कलेक्टर के सोच को रद्दी की टोकरी में डालकर अपराध को संरक्षित किये बैठे है वह शमर्नाक है।

प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे ने प्रमाण सहित बताया कि महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी सहायिका पद में ग्रेड अंकसूची का फर्जी अंक निर्धारण करा अपात्र को नियुक्ति देकर विभाग ने फर्जीवाड़ा किया अंक सूची के संबंध में शिकायत होने पर डी ई ओ द्वारा गठित जांच दल ने उस अंक सूची के अंक निर्धारण को गलत प्रमाणित किया है नियुक्ति के पहले ही इस संबंध में शिकायत किए जाने पर विभाग अपनी कारगुजारियों से फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा कर आर्थिक अनियमितता किए हैं। विभाग संलिप्त आरोपियों को बचाने एड़ी चोटी लगाए है इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में फर्जी टेक्निशियनों की नियुक्ति के मामले में दस्तावेजों सहित शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठकर जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का संकल्प लिए बैठे हैं। आबकारी विभाग तो राजस्व के नाम पर अवैध दुकाने नियम की धज्जियां उड़ाकर खोले बैठे हैं राजनांदगांव में जितने भी प्रीमियम या कम्पोजिट शराब दुकान चल रहे हैं उन भवनों का ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग से भवन का मूल्यांकन है और तो और निगम से भवन अनुज्ञा भी नहीं होने के साथ भाड़ा नियंत्रण विभाग से किराया भी फिक्स नहीं कराया गया है जबकि सरकारी नियमों में किराए के भवन का भाड़ा नियंत्रण से किराया फिक्सेशन कराना अनिवार्य प्रावधान है अवैध धान, अवैध खनिज पकड़ कर फोटो खींचाने वाले एक भी अवैध परिवहन करने वाले वाहन को राजसात नहीं कर अवैध कार्यों में लगे रसूखदारों को बचाने का काम किये हैं। फर्जीवाड़ा अवैध काम का हर विभाग में लंबी फेरहिस्त है जिससे अपराध व अपराधियों के हौसले बुलंद है।

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2025 : 10307 परीक्षार्थियों के लिए बनाए थे 25 परीक्षा केन्द्र

नेत्रहीन नेहा भी बनेगी अफसर, – पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुई

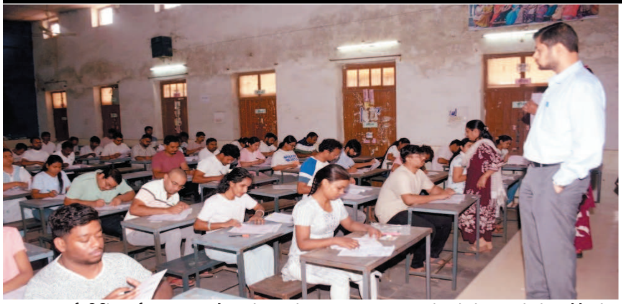

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित की गई। दुर्ग/भिलाई के विभिन्न 25 परीक्षा केंद्रों में प्रतिभागी परीक्षार्थी सम्मिलित हुये। इन्हीं में से एक नेहा यमराज भी है जो नेत्रहीन होने के बावजूद अपने बुलंद हौसले के साथ परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0505 सेजेस जेआरडी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग पीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने पहुंची थी। अपनी मेहनत से अधिकारी बनने की ख्वाइस रखने वाली नेहा के लिए जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केन्द्र में पृथक कक्ष व लेखन कार्य हेतु सहयोगी की व्यवस्था की गई है। उक्त कार्य में काजल बंजारे जो 11वीं की छात्रा है, नेहा को सहयोग करेगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने नेहा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने केन्द्राध्यक्ष को कक्ष में प्रकाश, पेयजल एवं इमरजेंसी लाइट प्रबंध करने निर्देशित किया।

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2025 की परीक्षा रविवार 22 फरवरी को दुर्ग, भिलाई नगर के 25 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। 10307 परीक्षार्थियों के लिए दो पालियों (क्रमशः सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक) में परीक्षा आयोजित की गई।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त परीक्षा के प्रथम पाली में परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0503 उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0504 शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या पीजी कालेज दुर्ग, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0505 सेजेस जेआरडी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग, परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0523 आमदी नगर विद्या निकेतन हायर सेकण्डरी स्कूल हुडको भिलाई और परीक्षा केन्द्र क्रमांक 0525 भिलाई महिला महाविद्यालय सेक्टर 9 भिलाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने केन्द्राध्यक्ष को लोक सेवा आयोग के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करते हुए बेहतर ढंग से परीक्षा संचालित करने निर्देशित किया। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा कक्ष एवं परीक्षार्थियों की संख्या, प्रकाश, इमरजेंसी लाइट, पेयजल, वाशरूम, परीक्षा कक्ष प्रवेश पूर्व परीक्षार्थियों की चेकिंग, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र के साथ वीडियोग्राफी आदि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने केन्द्र को उपलब्ध प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका सीट की भी जानकारी ली। उन्होंने परीक्षा समाप्ति पश्चात बरते जानी वाले सावधानियां पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश केन्द्राध्यक्ष को दिए। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्रों के लिए नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने बूथ कार्यकताओं के साथ सुनी मन की बात

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने टंकी मरोदा वार्ड 14, बूथ नंबर 243 में कार्यकताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 131वीं कड़ी का श्रवण किया। इस अवसर पर जिला मंत्री शैलेन्द्र शेंडे, मरोदा पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू राकेश जंघेल, पार्षद सरिता देवांगन, बूथ अध्यक्ष गैंद लाल जंघेल, सरोज साहू, प्रमिला निषाद, टिंकी, गायत्री निर्मलकर, रूपा निषाद, लक्ष्मी निषाद, तीज बाई कुर्रे, तीज बाई ढीमर, गायत्री, उषा ठाकुर, सकुन ठाकुर, सेजा साहू, बिसाहीन निषाद, इन्द्रा साहू, लीला सेन, सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम की 131वीं कड़ी में देश को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। - छात्रों को मंत्रः पीएम मोदी ने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे परीक्षाओं में नंबरों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और शिक्षकों व अभिभावकों से संवाद बनाए रखें। त्योहार और स्वदेशीः आने वाले होली और रमजान के त्योहारों के लिए शुभकामनाएं दीं और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने (Vocal for Local) पर जोर दिया। - एआई (अक) और साइबर सुरक्षाः टेक्नोलॉजी के दौर में अकके प्रभाव और साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहने की बात की। - गुलामी के प्रतीक हटेः पीएम मोदी ने बताया कि देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व दे रहा है।

इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में छिपी हुई प्रतिभाओं को जानने और पहचानने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी विकास की नई गाथा लिखी जा रही है।" कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में बुद्ध व अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शहर के हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित डॉ बाबा साहेब बुद्धिस्ट सांस्कृतिक समिति धम्म भूमि में शनिवार को भगवान बुद्ध और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भंते डॉक्टर वेनरेबल शील रत्न बोधि ने अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएसपी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ उदय कुमार ने इसे एक अनुकरणीय पहल बताया।

उल्लेखनीय है कि दानवीर आयुष्मान अशोक धवले ने अपने जन्मदिन पर यह दो प्रतिमाएं दान कर उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। उन्होंने यहां महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की धम्म मार्ग पर चल रही 6 फुट से ऊंची प्रतिमा दान कर स्थापित की और विश्व रत्न डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित करवाई है।

आयोजन में मुख्य संरक्षक सुनील रामटेके, संरक्षक एल. उमाकांत, विनोद वासनिक, राजेश बंजारी, वर्षा बागडे, नरेंद्र शेन्डे, प्रमुख संरक्षक अशोक धवले, अध्यक्ष वीरेन्द्र नागदेव, राजेश कांबले, धम्म सेवक संदीप चौरे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर त्रिशरण पंचशील और बुद्ध वंदना का पाठ के साथ प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण जय भीम और जय बुद्ध के नारों से गूंजता रहा।

इस अवसर पर डॉ बाबासाहेब बुद्धिस्ट सांस्कृतिक समिति हाउसिंग बोर्ड भिलाई के अध्यक्ष डिलेंद्र नागदेवे, उपाध्यक्ष बसंत धारगावे, सचिव राजेश कांबले, सहसचिव धनंजय बड़गे, कोषाध्यक्ष गिरीश रामटेके, कायर्कारिणी सदस्य मिलिंद रामटेके, आनंदपुर घोड़गे, प्रकाश गजबे, धम्म सेवक संदीप चौरे, सदस्य मनोज बागडे, संरक्षक राजेश बंजारी, संजय बागडे, सदस्य शीतल सिंगाड़े, कार्यकर्ता सुरेंद्र मंडपे, दशरथ मेश्राम, तुकाराम करवादे, आशीष चौरे, नरेंद्र फुलझेले, चंद्रशेखर जनबंधु, विजय घोड़के, मनीष मेश्राम, दिनेश शेंडे, डॉ बाबासाहेब बुद्धिस्ट सांस्कृतिक समिति महिला मंडल समिति से अध्यक्ष कविता वानखेडे, उपाध्यक्ष चेतन बड़गे, सचिव अचर्ना गजभे, कोषाध्यक्ष निमर्ला धारगांवें, ज्योति खोबरागड़े सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने दिव्यांगों को दिया स्कूटी, लाभार्थियों में हर्ष का माहौल

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने विधायक कार्यालय कवर्धा में दो दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमरौडी निवासी धरम सिंह पटेल और ग्राम खिरसाली निवासी उलख राम पटेल को स्कूटी की चाबी सौंपकर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को सुगम करना है। स्कूटी मिलने से लाभार्थियों को आवागमन में सुविधा होगी तथा वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे।

इस अवसर पर धरम सिंह पटेल ने बताया कि वे विद्युत विभाग में अस्थाई रूप से ऑपरेटर का कार्य करते हैं। पहले उन्हें कार्य में जाने में बहुत असुविधा हुआ करती थी आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन में किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, अब स्कूटी मिल जाने से वे अपने अनुसार कार्य पर जा आ सकेंगे। उलख राम पटेल ने बताया कि वे कपड़े सिलने का कार्य करते हैं ऐसे में स्कूटी मिल जाने से उन्हें अपने कार्य में बहुत आसानी होगी। दोनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं शासन–प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें स्कूटी उपलब्ध कराई गई जिससे वे खुश हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दोनों को वाहन चलाने का भी अभ्यास करवाया और दोनों का स्वागत कर उत्साहवर्धन किया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि सभी नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

उल्लेखनीय है कि अब तक उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल से 100 से अधिक दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण लगे स्कूटी प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य भगतराम पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, नरेन्द्र मानिकपुरी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, भुखन साहू, रामबिलास चंद्रवंशी, विजय पाटिल रवि राजपुत, श्रीमती सतविंदर पाहुजा, श्रीमती विजय लक्ष्मी तिवारी, लाला राम साहू सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार स्तंभ - धीरज बाकलीवाल

ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन सृजन के तहत पश्चिम ब्लाक की हुई पहली बैठक

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पश्चिम ब्लॉक की प्रथम बैठक राजीव भवन दुर्ग में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने की बैठक में नवनियुक्त ब्लाक अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार को उनकी नियुक्ति पर सभी नेताओ ने बधाई दी।

अध्यक्ष कर रहे हैं धीरज बाकलीवाल ने कहा कि संगठन में हमारे ब्लॉक स्तर के वार्ड स्तर के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के आधार स्तंभ है। इस विधानसभा चुनाव में भी सभी सर्वे सब में कांग्रेस की जीत बताया था। लेकिन भाजपा के दुष्प्रचार और जनता से झूठे वायदे कर चुनाव जीत तो लिया लेकिन आज तक अपनी घोषणाओं और वादों को भाजपा पूरा नहीं कर पाई। प्रदेश के भाजपा शासन से किसान, युवा, महिला, व्यापारी हर वर्ग निराश है। भाजपा के वायदा खिलाफी और जनविरोधी कार्यों को वार्ड और बूथ स्तर में आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता को करना है।

प्रदेश महामंत्री दीपक दुबे ने कहा कांग्रेस संगठन सीजन के तहत पुराने और युवा कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए संगठन में पद दिया। दुर्ग शहर में धीरज बकरीवाल के रूप में युवा जिला अध्यक्ष देकर युवाओं में नए उत्साह की भावना को बढ़ाया है। आनंद कपूर ताम्रकार स्कूल जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए और हर कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी उपस्थित का परिणाम है कि आज उन्हें ब्लॉकअध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है।

बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद पूर्व सभापति राजेश यादव प्रदेश सचिव अयूब खान वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी प्रवक्ता नासिर खोखर, ब्रिज लाल पटेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सैयद अनीश रजा ने किया।

बैठक में प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय धीरज बाकलीवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक दुबे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान, पूर्व सभापति राजेश यादव, छाया महापौर श्रीमती प्रेमलता साहू, पूर्व पार्षद अब्दुल गनी, पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सुश्री जमुना साहू, मध्य ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पूर्व पार्षद बृजलाल पटेल, फतेह सिंह भाटिया, पोषण साहू, उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती देवश्री साहू, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह भाटिया, पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार, मंडल अध्यक्ष विजयंत पटेल, नंदकिशोर शर्मा, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नासिर खोखर, विधि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम देशमुख, शिशिरकांत कसार, सुनीत घोष, श्रीमती पिंकी ठाकुर, श्रीमती अंकित राजपूत, श्रीमती लक्ष्मी सिंहा, श्रीमती धनवंती निषाद, बृजमोहन तिवारी, देव सिंहा, विजेंद्र भारद्वाज, गौरव सेन, हरीश सिन्हा, चिराग शर्मा, इसाक अली, संतोष सोनी, अनिल देवांगन, अविनाश यादव, तिलक सिंह राजपूत बुलाकी ठाकुर, मुकेश निर्मलकर, आसिफ अली भीमा चौहान, सुरेश जंघल, नईम खान, विनोद साहू विष्णु निषाद, मुकेश साहू, संघर्ष हिरवरकर, संजय बत्रा, विनोद सेन, मोहित वालदे, रोहित ताम्रकार, विनोद राणा खुर्शीद अहमद सुरेंद्र सिंह राजपूत, रवि कोसरिया, अली असगर बैठक कार्यक्रम का संचालन सैयद अनीस रजा ने किया।

कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक धरम लाल कौशिक, विधायक धमर्जीत सिंह, विधायक अजय चंद्राकर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज

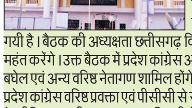

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज होगी प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक। यह बैठक शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आहुत की गयी है। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत करेंगे। उक्त बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। उक्त बैठक की जानकारी छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पीसीसी से संबद्ध नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के मीडिया प्रभारी घनश्याम राजू तिवारी ने दी है।

टनल इंजीनियरिंग कर अपने भविष्य को दें दिशा

अगर टनल इंजीनियर शब्द आपके लिए नया है, तो बता दें हम आपको इस फील्ड से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं। टनल इंजीनियरिंग का कोर्स कर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों का टनल से तो वास्ता जरूर होता होगा। टनल ट्रांसपोटेशन इन्फास्ट्रक्चर का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है। इंजीनियर और एक्सपर्ट्स मिलकर टनल को तैयार करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट टनल इंजीनियरिंग है। यह जियोटेक्निकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। बता दें कि टनल इंजीनियर को चट्टानों व मिट्टी की काफी अच्छी समझ होती है। आपको बता दें कि आप टनल इंजीनियरिंग कर अपने भविष्य को एक दिशा दे सकते हैं। अगर टनल इंजीनियर शब्द आपके लिए नया है, तो बता दें कि यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि टनल इंजीनियर कैसे बनते रहैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए और इसमें जॉब की क्या संभावनाएं होती हैं।

योग्यता

यदि कोई युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होगी। इसके बाद वह टनल कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक करने के बाद आप टनल बोरिंग की तकनीकों में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के विश्वविद्यालय टनल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा बीटेक-एमटेक करने के बाद भी आप टनल इंजीनियर बनने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।

सैलरी

भारत देश में एक टनल इंजीनियर की एवरेज सैलरी करीब 1,73,615 रुपए के महीने के आसपास होती है। हांलाकि नॉलेज, स्किन और एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रोथ मिलती रहती है। ऐसे में युवा इस फील्ड में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।

ई-मेल मार्केटिंग में बना सकते हैं शानदार कॅरियर

वर्तमान समय में ईमेल के जरिए हर कंपनी मार्केटिंग अभियानों को कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि ग्राहकों के लिए ई-मेल मार्केटर ऐसी कॉपी लिखते हैं। जो कस्टमर को कंपनी के साथ इंगेज कर सके। इसके लिए ईमेल मार्केटर हर ईमेलर के लिए स्ट्रैटली तैयार करते हैं। वह कंटेट से लेकर ग्राफिक्स तक तैयार करवाते हैं। इस काम के लिए कंपनियां बड़ी संख्या में डिजिटल कंटेट राइटर, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर और लीड ईमेल कंटेंट मार्केटर हायर करती हैं।
ऐसे में आप भी इस क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाकर घर बैठे काम सीख सकते हैं। इसके जरिए कंपनियां हफ्ते भर में होने वाली गतिविधियां न्यूजलेटर के जरिये ग्राहकों को हर हफ्ते भेजती रहती हैं। जिस कारण ईमेल मार्केटिंग आज एक बड़ी फील्ड के तौर पर उभरा है। ऐसे में अगर आप भी ईमेल मार्केटिंग करना जानते हैं, तो आप इस फील्ड में आसानी से लाखों का पैकेज उठा सकते हैं। इस फील्ड में कॅरियर बनाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको इस फील्ड से संबंधित सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या होती है ई-मेल मार्केटिंग

आपको बता दें कि यह एक कमर्शियल मैसेज की तरह होता है, जिसके इस्तेमाल से कंपनी सीधे तौर पर कस्टमर को टारगेट करती है। इसकी मदद से कंपनी कस्टमर को अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देने के साथ उसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम करती है। यही कारण है कि ई मेल मार्केटिंग का कन्वर्जन रेट बाकी मार्केटिंग तरीकों की तुलना में ज्यादा होता है। वहीं कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस काम को घर बैठे भी कर सकते हैं। ई-मेल मार्केटिंग में आप एक साथ सैकड़ों लोगों को कंपनी का मेल भेज सकते हैं।

ई-मेल मार्केटिंग का लक्ष्य

- अपने बिजनेस वेबसाइट को प्रमोट करना
- नए ऑफर्स की जानकारी कस्टमर्स को देना
- अपने उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाना
- अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना

कैसे करें ई-मेल मार्केटिंग

अगर आप भी इस फील्ड में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ई-मेल अकाउंट होना चाहिए। वर्तमान समय में तमाम कंपनियां ई-मेल के जरिए अपने मार्केटिंग अभियान को चलाती हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास ई-मेल लिस्ट, मार्केटिंग टूल्स सेटअप होने के साथ ई मेल टेम्प्लेट भी होना भी जरूरी है।

ई-मेल मार्केटिंग कोर्स के लाभ

- ई-मेल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस या उत्पाद को प्रमोट कर सकते हैं।
- एक ही समय में आप कई लोगों को ई-मेल भेजने का काम कर सकते हैं।
- साथ ही आपके मेल को किसने देखा और किसने स्पैम किया, आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं।
- बता दें कि इसका कनवर्जन रेट काफी ज्यादा है।
- आप बेहद कम बजट के साथ यह मार्केटिंग कर सकते हैं।
- इसमें कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से संवाद कर सकते हैं।

सैलरी

आपको बता दें कि इस फील्ड में कॅरियर बनाने वाले युवाओं को सालाना 6 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है। वहीं एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही सैलरी में इंक्रिमेन्ट होता रहता है।

आज के समय में कंपनियां बड़ी संख्या में डिजिटल कंटेट राइटर, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर और लीड ईमेल कंटेंट मार्केटर हायर करती हैं। ऐसे में आप भी इस क्षेत्र में अपना शानदार कॅरियर बना सकते हैं।

कोर्स की खासियत

- गूगल सर्टिफाइड अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षण
- साप्ताहिक डाउट क्लीयरिंग सेशन
- 100 घंटे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस
- एक्सपर्ट्स के साथ मास्टर क्लास
- 100 फीसद प्लेसमेंट असिस्टेंस
- 20 से ज्यादा लर्निंग टूल्स
- 8+ लाइव प्रोजेक्ट्स
- कम्प्लीमेंट्री कोर्स-सॉफ्ट स्किल्स

कॅरियर को मिलेगी नई दिशा

युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट, प्रोफेशनल और और लॉन्ग टर्म कोर्सेज की शुरुआत की गई है। बता दें कि डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कई ऐसे कोर्स हैं, जिनको करके युवा अपने कॅरियर को नई दिशा दे सकते हैं।

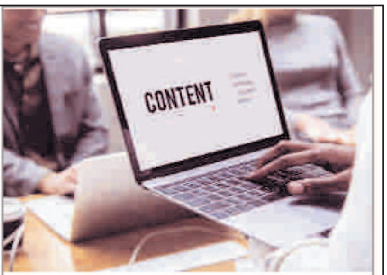

कंटेंट मार्केटिंग के जरिए हर कंपनी बन रही बेस्ट

युवाओं के लिए हैं कई अवसर

कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए कंटेंट का सहारा लेती है। कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट के लिए प्रचार करने का एक हिस्सा होता है। जिसे कंपनी के लिए काम करने वाले कंटेंट राइटर्स द्वारा किया जाता है।

अगर आप भी हर रोज अपने मोबाइल में तमाम विभिन्न कंपनियों द्वारा भेजे गए दर्जनों मैसेज, नोटिफिकेशन्स और व्हाट्सअप मैसेज और ईमेल्स को देखते होंगे। यह कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट के लिए प्रचार करने का एक हिस्सा होता है। जिसे कंपनी के लिए काम करने वाले कंटेंट राइटर्स द्वारा किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी कंपनी को तेजी से ग्रोथ पाने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है। कंटेंट के जरिए ही बिजनेस लोगों के बीच पहचाना जाता है, जो धीरे-धीरे ब्रांड बन जाता है। यही कारण है कि साल 2026 तक कंटेंट मार्केटिंग का सेक्टर अपने वार्षिक रिवेन्यू को डबल करने जा रहा है। वहीं अगर साल 2023 के कंटेंट मार्केटिंग रिवेन्यू की बात की जाए, तो सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग कंपनियों ने 66 बिलियन यूएस डॉलर गेन करने का काम किया है। ऐसे में अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और अपने के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

कंटेंट मार्केटिंग में स्कोप

- वर्तमान समय में कंटेंट ही किंग है।
- हर फील्ड की कंपनियां अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए कंटेंट का सहारा लिया जाता है।
- साल 2019 से 80% कंपनियां कंटेंट के जरिए मार्केटिंग कर रही हैं।
- साल 2021 में 97% कंपनियां कंटेंट के माध्यम से मार्केटिंग करना शुरू कर चुकी हैं।
- वहीं 40% मार्केटर्स ने साल 2022 में कंटेंट मार्केटिंग का बजट बढ़ाया है।
- जो युवा इस फील्ड में कॅरियर बनाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ ही सैलरी बढ़ती रहती है।
- बता दें कि कंटेंट मार्केटर की शुरूआती सैलरी 25,000 रुपए महीना होती है।

कस्टमर को कैसे दें प्रोडक्ट की जानकारी

हर फील्ड में कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को कई तरीके से जानकारी दी जाती है। आप वीडियो, जीआईएफ, ब्लॉग पोस्ट, इंफोग्रॉफिक, ईमेल न्यूजलेटर के जरिए कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। वहीं कस्टमर को जागरुक करने का सबसे प्रभावी तरीका प्रोडक्ट के बारे में तैयार किया गया ऑडियो विजुअल फॉर्मेट है। जोकि सबसे ज्यादा प्रचलन में है।

डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम की खूबी

डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाकी संस्थानों की अपेक्षा कम कीमत में मिलता है। इस फील्ड में आपको 40 से अधिक टूल्स और मॉड्यूल्स के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, गूगल एड, ई-मेल मार्केटिंग, फेसबुक एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्रॉफ़िक्स डिजाइन, एंटरप्रेंन्योरशिप स्किल भी सिखाई जाती हैं। इसमें कैंडिडेट को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही कैंडिडेट को 2 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है।

जॉब

- पे पर क्लिक एक्सपर्ट्स
- सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
- सोशल मीडिया मैनेजर
- एफिलिएट मार्केटिंग
- गूगल एड एक्सपर्ट्स
- ई-मेल मार्केटिंग

मेधावी छात्रों को कोलगेट दे रहा बंपर स्कॉलरशिप

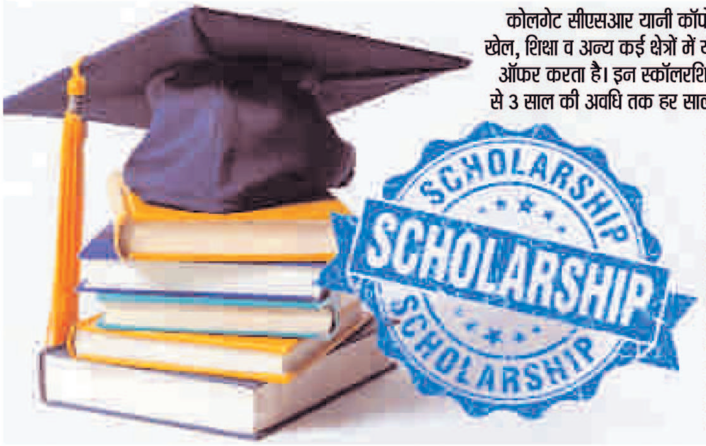

कोलगेट सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत खेल, शिक्षा व अन्य कई क्षेत्रों में योगदान के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है। इन स्कॉलरशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को 2 से 3 साल की अवधि तक हर साल 75,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

कोलगेट देश की सबसे बड़ी दंत मंजन कपनियों में से एक है। यह कंपनी सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत खेल, शिक्षा व अन्य कई क्षेत्रों में योगदान के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है। इस प्रोग्राम का नाम कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को अपने सपने को पूरा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा मेधावी छात्रों को उचित मेंटरशिप भी प्रदान करता है।
आपको बता दें कि कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन के तहत उम्मीदवारों का चयन विभिन्न स्कॉलरशिप के लिए किया जाता है। इन स्कॉलरशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को 2 से 3 साल की अवधि तक हर साल 75,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए 11वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। हांलाकि अलग-अलग क्लास के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं।

क्वालिफिकेशन

- इस स्कॉलरशिप का लाभ वर्तमान में बीडीएस पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में नामांकित छात्र ले सकते हैं।
- छात्रों को न्यूनतम 60% अंकों के साथ कक्षा 12 की परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
- आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट स्नातक बीडीएस संस्थान में नामांकित होना चाहिए।
- छात्र के परिवार की सालान वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।
- यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।

डॉक्यूमेंट्स

- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- आय प्रमाण (फॉर्म 16ए/सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र/वेतन पर्ची, आदि)
- छात्रवृत्ति आवेदक का बैंक खाता विवरण (रद्द चेक/पासबुक कॉपी)
- प्रवेश का प्रमाण (कॉलेज आईडी कार्ड/बोनाफाइड प्रमाणपत्र, आदि)
- पिछली कक्षा की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की शुल्क रसीद
- फोटो पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
- विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

स्कॉलरशिप का लाभ

इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 11वीं के छात्रों को 2 साल तक 20,000 रुपए, ग्रेजुएशन व डिप्लोमा धारक छात्रों को तीन सालों तक 30,000 रुपए, अंडरग्रैजुएट/इंजिनियरिंग के स्टूडेंट्स को 4 सालों तक 30,000 रुपए, वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्रों को 1 साल तक 20,000 रुपए और स्पोर्ट्सपर्सन को 3 सालों तक 75-75 हजार रुपये मिलेगा।

जॉन अब्राहम को क्यों करना पड़ा आलोचना का सामना

जॉन अब्राहम ने हाल ही में बताया कि बॉलीवुड में बाहर से आने के कारण उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। यही नहीं जब वे फिल्मों में आए, तब इंडस्ट्री में बाहरी कलाकार बहुत कम थे। उससे पहले सिर्फ शाहरुख खान और अक्षय कुमार के अलावा कुछ ही स्टार्स बाहर से आकर कामयाब हुए थे।

आलोचना मिलने पर जॉन को कैसा लगा था

स्क्रीन मास्टरक्लास में एक बातचीत के दौरान जॉन ने कहा, 'मेरे समय में शायद सबसे ज्यादा आलोचना मुझे ही मिली। मैंने इसे आसान बना लिया था। मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देता था, जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ने वाला घोड़ा। मेरे पास कभी पब्लिसिस्ट नहीं रही और मैं किसी के भी आगे अपनी इमेज बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता।'

को-स्टार्स को लेकर जॉन की राय

जॉन ने बताया कि वे दूसरे स्टार्स को प्रतियोगी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथी मानते हैं। उन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, वरुण धवन और अभिषेक बच्चन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं। उनका मानना है कि मेल कलाकारों के साथ काम करना उन्हें बहुत सहज लगता है।

जॉन की आने वाली फिल्म

बहरहाल, जॉन अभी एक अच्छी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं। वे 'नो स्मोकिंग 2' बनने पर उसमें काम करने के लिए तैयार हैं। आखिरी बार उन्हें 'तेहरान' फिल्म में देखा गया, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इसके अलावा वे एक डॉक्यूमेंट्री 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जॉन, राकेश मारिया की बायोपिक और 'फोर्स 3' में काम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

प्रियंका और दीपिका के बाद बाफ्टा अवॉर्ड के स्टेज पर नजर आएंगी आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने बाफ्टा अवॉर्ड में शामिल होने की बात फैंस के साथ साझा की है। उन्होंने बाफ्टा के इंस्टाग्राम पेज की पोस्ट को अपनी स्टोरी पर लगाया। साथ ही लिखा, '100 प्वाइंट्स दूंगी, अगर आप मुझे यहां खोज लें।' इस बाफ्टा पोस्ट में कई लोगों की फोटो हैं, जिसमें आलिया की फोटो भी शेयर की गई है।

बाफ्टा में आलिया बनेंगी प्रेजेंटर ब्रिटिश एकेडमी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा की। जिसके जरिए बताया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में शामिल होंगी। वह इसमें बतौर प्रेजेंटर शामिल हो रही हैं। बाफ्टा अवॉर्ड देने की जिम्मेदारी कई अन्य कलाकारों के साथ वह भी निभाएंगी।

आलिया से पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण बनीं प्रेजेंटर

आलिया भट्ट बाफ्टा के स्टेज पर बतौर प्रेजेंटर नजर आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हैं। उनसे पहले देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण भी पिछले वर्षों के बाफ्टा अवॉर्ड में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुईं। इस साल आलिया के अलावा कई ब्रिटिश और हॉलीवुड एक्टर्स भी बाफ्टा में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगे। इसमें एलिसिया विकेंडर, ब्रायन क्रैंस्टन, सिलियन मर्फी, डेलरॉय लिंडो, एमिली वॉटसन, एथन हॉक, गिलियन एंडरसन, ग्लेन क्लोज, हन्नाह वाडिंगहैम, मोनिका बेलुची, रेगे-जीन पेज, रिज अहमद और स्टेलन स्कारगार्ड भी शामिल हैं।

कब होगी अवॉर्ड सेरेमनी?

बाफ्टा अवॉर्ड सेरेमनी चंद दिनों में ही होने वाली है। यह अवॉर्ड फंक्शन लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 22 फरवरी को आयोजिन होगा इसमें अंतरराष्ट्रीय सिनेमा जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। कई चर्चित फिल्मों को अवॉर्ड दिए जाएंगे।

प्रियंका चोपड़ा को ऐश्वर्या और इरफान खान से मिली हॉलीवुड जाने की प्रेरणा

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा हाल ही में सालाना हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचीं। यहां उन्होंने अपने देश और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंचने के अपने सफर पर चर्चा की। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया। साथ ही वे हॉलीवुड तक पहुंचीं, इसका क्रेडिट ऐश्वर्या राय और इरफान खान सरीखे सितारों को दिया। प्रियंका का कहना है कि इन सितारों ने हॉलीवुड के रास्ते खोले।

प्रियंका ने शेयर किया इमोशनल नोट

प्रियंका चोपड़ा ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अपने करियर और हॉलीवुड तक के सफर का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने हॉलीवुड में रास्ता बनाने का क्रेडिट ऐश्वर्या राय, इरफान खान और मिंडी कालिंग को दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट भी शेयर किया है। इसमें अपनी करियर जर्नी पर एक इमोशनल नोट लिखा है।

इन हस्तियों ने दूसरों के लिए रास्ते आसान बनाए

प्रियंका चोपड़ा ने यह स्वीकार किया कि किस तरह एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, दिवंगत एक्टर इरफान खान और अमेरिकन एक्टर-कॉमेडियन मिंडी कालिंग के सफर ने हॉलीवुड में उनके अपने करियर में योगदान दिया। उन्होंने इन पर्सनैलिटीज को ट्रेलब्लेजर बताया, जिनकी कामयाबियों ने दूसरों के लिए रास्ते तैयार किए। उनके नक्शेकदम पर चलना मुमकिन बनाया।

प्रियंका ने जाहिर किया उत्साह

प्रियंका चोपड़ा ने साझा किए गए पोस्ट के साथ लिखा है, 'मेरे दिन की शुरुआत ऐसे हुई। मुझे अपनी सबसे करीबी दोस्तों और बिजनेस पार्टनर अंजुला आचार्य के साथ मशहूर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंडिया वीक खत्म करने के लिए एक फायरसाइड कीनोट एड्रेस देना था। टॉपिक था 'जैसा इंडिया हम सोचते हैं'। यहां ऑडियंस में देखते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, 'तुम वही इंडिया हो, जिसकी मैंने कल्पना की थी'। प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी।

ऋचा ने बयां किया करियर का शुरुआती

अनुभव, भरोसेमंद व्यक्ति ने दिया था धोखा

अभिनेत्री और निर्माता ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत के दौरान एक कड़वे अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति पर वह बहुत भरोसा करती थीं, उसने उनके हितों के खिलाफ काम किया और उन्हें धोखा दिया था। ऋचा ने बताया कि इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि हर कोई आपका ध्यान नहीं रख सकता या आपके बारे में नहीं सोच सकता। ऋचा ने कहा, 'अपने करियर की शुरुआत में मुझे यह कड़वा सबक मिला कि हर कोई आपका इतना ध्यान नहीं रखता। मैं भोली थी। कुछ लोग थोड़े से अंतर से भी खतरा महसूस करते हैं और नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाएं या उनकी स्पॉटलाइट छीन लें।' यह अनुभव उनके लिए काफी परेशान करने वाला था, लेकिन इससे उन्होंने अपनी पसंद का बचाव करना और सही लोगों पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह उनसे संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। आम धारणा है कि बड़े एक्टर्स से अप्रोच करना मुश्किल होता है, लेकिन ऋचा ने इसे गलत बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'एक सोच है कि हमसे संपर्क करना कठिन है, लेकिन यह सच नहीं। मेरे लिए सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट, सच्ची राइटिंग और कहानी का असर मायने रखता है। मैं हमेशा सही कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं।' ऋचा ने शुरुआती दिनों में कम आंके जाने की बात भी कही। वह चाहती हैं कि इंडी क्रिएटर्स बिना झिझक के अच्छे रोल और कहानियों के लिए संपर्क करें। ऋचा एक नई नॉन-फिक्शन सीरीज का निर्माण कर रही हैं। इसके जरिए ऋचा का मकसद दर्शकों को जानी-पहचानी जगहों को नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही कम जानी-पहचानी कहानियों को उजागर कर भारत की सांस्कृतिक गहराई और इंसानी जज्बे को सेलिब्रेट करना है।

एक्टर्स और उनकी टीम की बढ़ती फीस चिंता की बात

अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले निर्देशक अनुभव सिन्हा इंडस्ट्री और सिनेमा दोनों पर खुलकर राय रखते हैं। यूनिट के बढ़ते आकार से लेकर बॉक्स ऑफिस की बहस, बढ़ते बजट तक... बातचीत में उन्होंने हर सवाल पर बेबाकी से बात की।

कहानी से ज्यादा मैनेजमेंट चल रहा है

इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद अनुभव सिन्हा बदलाव को साफ नजर से देखते हैं। उनके मुताबिक समय के साथ बहुत कुछ बदला है। 'सबसे बड़ा बुरा बदलाव यह है कि यूनिट बहुत बड़ी हो गई है। पहले फिल्म बनाना शांत और निजी काम होता था। अब सेट पर बहुत लोग होते हैं, बहुत शोर होता है। कई बार लगता है कि कहानी से ज्यादा मैनेजमेंट चल रहा है।'

दर्शक थिएटर नहीं जाते, मैं यह नहीं मानता

वे यह भी मानते हैं कि बदलाव सिर्फ नकारात्मक नहीं हैं। 'अब फिल्मों में पैसा आ रहा है। लोग कहते हैं कि दर्शक थिएटर नहीं जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं हाल ही में कई शहरों में गया हूं। लोग फिल्में देख रहे हैं। कोविड के बाद भी कई फिल्में हजार करोड़ तक पहुंची हैं। इसका मतलब ऑडियंस हैं। रिटर्न बढ़े हैं, निवेश बढ़ा है। फाइनेंसिंग पहले से ज्यादा व्यवस्थित और साफ हुई है। इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, लेकिन अभी हम पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं बने हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं।'

फिल्में महंगी होती जा रही हैं

कलाकारों की बड़ी टीम और बढ़ते बजट पर वे साफ कहते हैं, 'हां, फिल्में लगातार महंगी हो रही हैं। अब सिर्फ कलाकार नहीं आते, उनके साथ पूरी टीम आती है और खर्च बढ़ता है। इस पर दोबारा सोचने और बात करने की जरूरत है। यह मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा, तो अच्छी फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा।'

अब एक प्रॉपर म्यूजिकल बनाना चाहता हूं

संगीत को लेकर उनका उत्साह आज भी बरकरार है। उन्होंने बताया 'मुझे सही मायने में एक म्यूजिकल फिल्म बनानी है। काफी समय हो गया है वैसा सुपरहिट म्यूजिक किए हुए, जो रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। 'रा.वन' के बाद मैंने उस तरह का म्यूजिक नहीं किया। 'तुम बिन', 'दस बहाने' और 'कैश' के गाने आज भी बजते हैं। कई लोगों को यह भी नहीं पता कि वह म्यूजिक मैंने बनाया था। अब मन है कि ऐसी फिल्म बनाऊं, जिसमें कहानी संगीत के साथ आगे बढ़े। गाने सिर्फ गाने न हों, कहानी का हिस्सा हों। मुझे लगता है म्यूजिक की ताकत बहुत बड़ी होती है।'

अनुराग कश्यप ने इस मामले में 'निशांची' को बताया 'सिनर्स' से बेहतर

निर्माता-निर्देशक व अभिनेता अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'कैनेडी' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बीच अनुराग कश्यप ने अपनी पिछली फिल्म 'निशांची' को बनाने पर गर्व जताते हुए इसके स्पेशल इफेक्ट्स को हॉलीवुड फिल्म 'सिनर्स' से भी बेहतर बताया है। 'निशांची' दो भागों में बंटी एक क्राइम ड्रामा है, जिसमें कानपुर में रहने वाले जुड़वां भाइयों बबलू और डब्लू की कहानी है।

अनुराग ने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए की रेड चिलीज की तारीफ

बातचीत के दौरान अनुराग ने कहा कि अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ काम करते हुए, मैं काम करने की एक नई शैली देख रहा हूं। यह शैली आ रही है और दक्षिण में हर जगह देखने को मिल रही है। वे वहीं पर शूटिंग और एडिटिंग करते हैं। वे एक दिन में एक ही सीन शूट करते हैं और शॉट्स नहीं लेते। मेरे लिए स्पेशल इफेक्ट्स के साथ 'निशांची' के दोनों भाग, जिनमें अभिनेता ने दो अलग-अलग तरह की दोहरी भूमिका निभाई है - जिस पर मुझे बहुत गर्व है। स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में सिल्वेस्टर और रेड चिलीज ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो वाकई कमाल है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह 'सिनर्स' से भी बेहतर है। वे सचमुच दो अलग-अलग लोग हैं और हमने दो महीने के अंतराल पर शूटिंग की। ऐसा नहीं था कि आप कपड़े बदलकर आ गए हों। यह सब वास्तविक था।

ऑस्कर में 'सिनर्स' ने हासिल किए रिकॉर्ड नॉमिनेशन

हॉलीवुड फिल्म 'सिनर्स' में माइकल बी जॉर्डन ने दोहरी भूमिका निभाई है, जिसमें उन्होंने जुड़वां भाइयों एलिजा स्मोक मूर और एलियास स्टैक मूर का किरदार निभाया है। इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए अभिनेता को अपना पहला ऑस्कर नामांकन मिला। रयान कूगलर द्वारा निर्देशित 'सिनर्स' ने 98वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में रिकॉर्ड तोड़ 16 नामांकन हासिल करके इतिहास रच दिया, जो किसी एक फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक नामांकन है।

ऐसी है 'निशांची' की कहानी

अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित 'निशांची' पिछले साल दो भागों में रिलीज हुई थी। इस क्राइम ड्रामा की कहानी कानपुर में रहने वाले दो भाइयों बबलू और डब्लू के ऊपर आधारित है। फिल्म का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था, जिसे क्रिटिक्स से तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद दूसरा पार्ट मेकर्स ने सीधे ओटीटी पर रिलीज किया था। इस फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में मोनिका पवार, वेदिका पिंटो, विनीत कुमार सिंह, कुमुद मिश्रा और जीशान अय्यूब प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं।

20 फरवरी को रिलीज होगी 'कैनेडी'

अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'केनेडी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। यह फिल्म 20 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होनी है। इससे पहले फिल्म का प्रीमियर 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। जहां इसे काफी सराहना मिली थी। इसके अलावा भी कई फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को काफी सराहा गया है। और इसे सात मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। मेलबर्न इंडियन 'कैनेडी' में राहुल भट्ट और सनी लियोन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

भिलाई में विकास कार्यों की सौगात : सांसद विजय बघेल ने किया विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। राज्य शासन की अधोसंरचना मद से स्वीकृत राशि से इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराए जाने की जानकारी दी गई।

सांसद विजय बघेल ने सेक्टर-9 , वार्ड क्रमांक 17 में सीमेंटकरण कार्य का भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 7 स्थित मैत्री उद्यान में डोम शेड कार्य की शुरुआत का शुभारंभ किया गया। वार्ड क्रमांक 15, अंबेडकर नगर, कैंप 1 भी विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त सुपेला

स्थित कैंप और होजरी मार्केट क्षेत्र में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क के पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इन सभी कार्यों के लिए राज्य शासन की अधोसंरचना मद से स्वीकृत राशि उपलब्ध कराई गई है। सांसद ने आश्वस्त किया कि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

विकास को नई गति देने की बात

इस अवसर पर विजय बघेल ने कहा कि भिलाई शहर के विभिन्न हिस्सों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता है। सड़क, सीमेंटकरण और डामरीकरण जैसे कार्य सीधे तौर पर नागरिकों की दैनिक जीवन गुणवत्ता से जुड़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चरणबद्ध तरीके से अन्य वार्डों में भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

जनता ने जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने विकास कार्यों के लिए सांसद का हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही स्थानीय स्तर की छोटी-छोटी मूलभूत समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और शीघ्र निराकरण की मांग की। नागरिकों ने भविष्य में भी संरक्षण और सहयोग मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर उनके प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित अनेक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इन विकास कार्यों से भिलाई के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना सुधार की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

खास खबर

संस्कारधानी में योजनाओं के दावों पर सवाल : तीन दिन से नहीं जला चूल्हा

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

विकास और जनकल्याण की चमकदार तस्वीरों के बीच एक बोलता चित्र कई असहज सवाल खड़े कर रहा है। शहर के अटल आवास क्षेत्र में रहने वाली एक अभावग्रस्त महिला के घ,र तीन दिन तक चूल्हा नहीं जला—यह दावा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो शासन के दावों को कठघरे में खड़ा करती दिखती है।

स्थानीय पत्रकार कमलेश सीमनकर द्वारा साझा की गई तस्वीर में महिला के सामने रखा राशन मानो व्यवस्था पर सीधा आरोप है। बताया गया कि महिला को न तो निराश्रित कार्ड मिला, न राशन कार्ड, और न ही महतारी वंदन जैसी योजनाओं का लाभ। सवाल उठता है—जब वर्षों तक प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं की गूंज रही, तो यह जरूरतमंद अब तक सिस्टम की नजरों से ओझल कैसे रही? प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहे डॉ. रमन सिंह के कायर्काल और वतर्मान जिम्मेदारियों के बीच यह घटना प्रशासनिक दावों पर आईना बनकर उभरी है। क्या जमीनी अमला योजनाओं की हकीकत से अनजान है, या फिर कागजों में दर्ज सफलता वास्तविक जरूरतों को ढक रही है?

इस बीच, समाजसेवी भावेश अग्रवाल द्वारा तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने से मानवीय संवेदना की मिसाल जरूर सामने आई, लेकिन यह राहत एक बड़ा प्रश्न छोड़ जाती है—क्या नागरिकों की बुनियादी जरूरतें अब व्यक्तिगत दान और सद्भाव पर निर्भर रहेंगी? संस्कारधानी और संस्थाओं की नगरी कहलाने वाले राजनांदगांव में यह दृश्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर तीखा प्रहार करता है। जरूरत है कि संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें, ताकि योजनाओं के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई पाटी जा सके।

बदला मौसम का मिजाज, कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी

भिलाई। लगातार बढ़ते तापमान के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लिया है। प्रदेश में फिलहाल कुछ हिस्सों में हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण का असर प्रदेश पर पड़ रहा है, जिससे नमी युक्त हवाएं प्रवेश कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 और 24 फरवरी को मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से अति हल्की वर्षा हो सकती है। एक-दो स्थानों पर बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव प्री-समर गतिविधियों की शुरुआत का संकेत हो सकता है। नमी और गर्मी के संयोजन से स्थानीय स्तर पर बादल बन सकते हैं, जिससे शाम या रात के समय छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है।

टीम राकेश का ऐलान : जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) की विस्तारित कार्यकारिणी घोषित, संगठन को मिलेगा नया संबल

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से बनी 51 पदाधिकारियों और 10 कार्यकारिणी सदस्यों की टीम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं संगठन विस्तार के तहत जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर द्वारा विस्तारित जिला कायर्कारिणी की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित की गई थी। यह सूची राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत तैयार की गई थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अनुमोदन उपरांत प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैन्दू द्वारा आज बहुप्रतीक्षित सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। घोषित कायर्कारिणी में कुल 51 जिला पदाधिकारी एवं 10 जिला कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। इस घोषणा से जिले की राजनीति में नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार हुआ है।

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय, अनुभवी एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपकर संगठन को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी की विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों को मजबूती से जनता के बीच रखेंगे।

घोषित पदाधिकारियों का संक्षिप्त परिचय

कोषाध्यक्ष :- विक्रांत अग्रवाल - संगठन के विश्वसनीय एवं सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छाया जिला पंचायत सदस्य है। पूर्व में जिला कांग्रेस के महामंत्री रह चुके है।

उपाध्यक्षगण :- जय प्रकाश चंद्राकर - जमीनी स्तर के अनुभवी नेता। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। महेंद्र वर्मा :- संगठनात्मक अनुभव से परिपूर्ण, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने में सक्षम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन के पूर्व अध्यक्ष रहे है। तरुण बिजौर :- लगातार आम जन को कांग्रेस से जोड़ने में सक्रिय, भूपेश बघेल सरकार में चर्म शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष रहे है। प्रमोद राजपूत :- सामाजिक सरोकारों से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता। जनहित के मुद्दों पर मुखर भूमिका निभाते रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी के पूर्व अध्यक्ष रहे है। रोहित कुर्रे :- संगठन के प्रति समर्पित। बूथ स्तर पर सक्रियता के लिए पहचाने जाते हैं। शमशीर कुरैशी :- अल्पसंख्यक समाज का मजबूत प्रतिनिधित्व। सामाजिक समरसता के पक्षधर, जिला पंचायत दुर्ग के पूर्व सदस्य रहे है। संतलाल बंजारे :- अनुसूचित वर्ग समाज के सक्रिय नेता। संगठन को जमीनी मजबूती प्रदान करेंगे। विशाल देशमुख :- ग्रामीण अंचल में सक्रिय उपस्थिति। संगठनात्मक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका। हीरा वर्मा :- लंबे समय से पार्टी से जुड़े समर्पित कार्यकर्ता। जनसंपर्क में दक्ष। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। निरंजन राजपूत :- संघषर्शील छवि के नेता। जनआंदोलनों में सक्रिय भागीदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं विभिन्न संगठन आत्मक पदों पर रहे हैं। रिवेंद्र यादव :- संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय, कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे हैं। श्रीमती टिकेश्वरी देशमुख :- महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक। महिला वर्ग को संगठित करने में सक्रिय भूमिका।

महामंत्रीगण :- प्रभारी महामंत्री :- राजीव गुप्ता :- छह बार के जिला महामंत्री रहे हैं , संगठन संचालन में अनुभवयुक्त। सभी प्रकोष्ठों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुरुषोत्तम तिवारी :- अनुभवी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता। संगठनात्मक रणनीति में दक्ष। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। श्रीमती जयश्री वर्मा :- महिला नेतृत्व का सशक्त चेहरा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय। जिला पंचायत दुर्ग की सभापति रही है। श्रीमती लक्ष्मी साहू :- ग्रामीण महिला वर्ग से मजबूत जुड़ाव। संगठन विस्तार में योगदान। ज्वाला प्रसाद साहू :- मेहनती एवं समर्पित कार्यकर्ता। कार्यक्रमों के सफल संचालन में सक्रिय। जवाहर यादव :- जमीनी कार्यकर्ता। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने में अग्रसर। जवाहर यादव उन नेताओं में शुमार है जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। भूपेश बघेल के बेहद विश्वास पात्र कार्यकर्ता माने जाते है।

रूपेश देशमुख :- संगठनात्मक कार्यक्रमों में लगातार उपस्थित रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। कृष्णा देवांगन - सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय, दुर्ग जिला के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता है। श्रीमती योगिता चंद्राकर :- महिला एवं युवा वर्ग को संगठित करने में सक्रिय भूमिका। पूर्व सरपंच रिसामा एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही है। जामवंत गजपाल :- समाज का प्रतिनिधित्व। संगठन को नई ऊर्जा देंगे। प्रदीप चंद्राकर :- सक्रिय एवं कर्मठ कार्यकर्ता। जनआंदोलनों में भागीदारी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। प्रकाश ठाकुर :- संगठन के प्रति समर्पित। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भुवन साहू :- सामाजिक सरोकारों से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता। रज्जाक खान - अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व। समन्वयकारी भूमिका में सक्षम। पूर्व में जिला कायर्कारिणी में रहे हैं। रवि प्रकाश ताम्रकार - ऊर्जावान नेतृत्व,संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय। राम सूर्यवंशी - जमीनी कार्यकर्ता, ग्रामीण विकास के मुद्दों पर मुखर, सतनामी समाज से ताल्लुक रखते हैं।

श्रीमती दुर्गा गजबे - महिला सशक्तिकरण की समर्थक। संगठन में सक्रिय सहभागिता। नगर कांग्रेस कमेटी अहिवारा की पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। पालेश्वर ठाकुर -लंबे समय से संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता। लगातार मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, ग्राम पंचायत मर्रा के पूर्व सरपंच रहे हैं।

सचिव – राजा राम गहिरवार, दुलेश्वर साहू, पवन पटेल, धर्मेंद्र साहू, नेहरू यादव,, ओम नारायण वर्मा, सुमित नारंग, नारायण निषाद, लोचन यादव, घनश्याम गजपाल, रोहित यादव, अभिषेक जांगड़े, श्रीमती सुमन वर्मा महेंद्र निषाद, मुकुंद पारकर, पिलेश्वर साहू, राजेश मानिकपुरी, बहादुर नेताम, राजेश साहू, हिम्मत लाल धीमर, कार्यकारिणी सदस्यगण :- श्रीमती जागृति साहू, कल्याण साहू, सुरेंद्र गायकोवाड़, श्रीमती संगीता ठाकुर, श्रीमती उत्तरा कोसर, अघनु पाल, श्यामाचरण मनहर, गज्जू साहू, बंटी वैष्णव और जनार्दन सेन शामिल हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन में सभी वर्गों, समाजों एवं क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले समय में किसान, युवा, महिला, श्रमिक एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आवाज बुलंद करेगी।

नवगठित कार्यकारिणी आगामी कार्यक्रमों, आंदोलनों एवं संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कांग्रेस परिवार में इस घोषणा को लेकर उत्साह का वातावरण है तथा संगठन को नई दिशा एवं नई गति मिलेगी। नई कार्यकारिणी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व केबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी बधाई प्रेषित करते हुए उम्मीद जताई है कि पार्टी को मजबूत बनाने पूरी टीम काम करेगी।

बिना बारिश बना 'तालाब' ! 32 करोड़ का सुपेला अंडर ब्रिज सवालों में, मशीन बैठी या सिस्टम फेल?

अस्थायी उपाय कब तक? क्या हर बार मशीन खराब होगी और बाद में पानी खींचा जाएगा?

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, फिर भी सुपेला अंडर ब्रिज पानी से लबालब। 32 करोड़ रुपये की लागत और लंबी निर्माण अवधि के बाद तैयार हुआ यह अंडर ब्रिज अब अपनी इंजीनियरिंग पर खुद ही सवाल खड़े कर रहा है। आखिर बिना बारिश के पानी आया कहां से?

रेलवे और निगम सूत्रों का दावा है कि अंडर ब्रिज के नीचे सोखता गड्ढा (संप वेल) बनाया गया है, जिसमें पानी जमा होता है और उसे बाहर निकालने के लिए मोटर पंप लगाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि पानी खींचने वाली मशीन खराब हो गई, जिसके चलते पानी भरता चला गया और पूरा अंडर ब्रिज जलमग्न हो गया।

लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से बने इतने महत्वपूर्ण मार्ग में बैकअप सिस्टम क्यों नहीं था? यदि एक मशीन बंद होते ही अंडर ब्रिज तालाब बन जाए तो इसे तकनीकी चूक नहीं तो और क्या कहा जाए? रोजाना करीब एक लाख लोगों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर इस तरह का जलभराव सीधे-सीधे सुरक्षा से खिलवाड़ है।

फिलहाल निगम अपनी सक्शन मशीन लगाकर पानी निकालने में जुटा है। लेकिन यह अस्थायी उपाय कब तक? क्या हर बार मशीन खराब होगी और बाद में पानी खींचा जाएगा?

स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि बिना बारिश के ही जब यह हाल है, तो मानसून में क्या स्थिति होगी? 32 करोड़ की परियोजना का यह हाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। जनता जवाब चाहती है— जिम्मेदार कौन है? और ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? बीते रात से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।